4193 Appropriation (Railways) Bill

The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1960-61 for the purposes of Railways, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Speaker: I will now put the clauses to the vote of the House.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, how can we have discipline in the House when the hon. Minister of Parliamentary Affairs is moving at the same time when you are on your legs.

Shri Narayanankutty Menon (Mukandapuram): He should be a model for everyone of us.

The Minister of Finance (Shri Morarji Desai): The hon. Member was standing at that time.

Shri Khushwaqt Rai (Kheri): Sir, is discipline meant to be observed only by this side?

Mr. Speaker: Order, order: I will now put the clauses to the vote of the House.

The question is:

"That clauses 1, 2 and 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Long Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 1, 2 and 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Long Title, were added to the Bill.

Shri Shahaawax Khan: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

Mr. Speaker: The question is:

(Interruption). An hon. Member does not know when I am going to

MARCH 10, 1961 Demand for Grants 4194 (Railways)

get up and standing somewhere by itself is not an offence or an act of indecorum. In such cases what is usually done is—I have noticed this even during the previous regime that is, before 1947—that as soon the Chair gets up the hon. Member, wherever he might be, sits down immediately.

Shri Hem Barua (Gauhati): That is what I had done.

Mr. Speaker: I know the hon. Member is very decorous. That is what hon. Members ought to do. I hope and trust that this will be observed strictly. It is a courtesy shown to each one of us and to the House as a whole.

Now, the question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

12.27 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS)-1961-62-contd.

Mr. Speaker: The House will now proceed with further discussion of Demand for Grant No. 1 in respect of the Budget (Railways) for 1961-62.

Shri Abdul Latif will kindly continue his speech.

भी प्रस्कुल सतीक (विजनौर) : मुहतरिक स्पीकर साहब, पेशतर इसके कि मैं प्रपनी तक़रीर का प्राग्राज करूं, मुझे एक बात बड़े प्रफ़सोस के साथ कहनी पड़ी है। मैं मुसलसल दो मान से इस मामले को ले कर तकरीर कर रहा हूं लेकिन मेरे किसी एक मुताल्वे को इस वक्त तक ना तो मंजूर किया गया है प्रौर न ही मुझे कोई इत्तला दी गयी कि उलका हथा हुआ मने अपनी तकरीरों में डिप्टी विनिस्टर माहब जौर मिनिस्टर साहब की सबज्यह घंद पीकों की तरफ़ दिलाई वी धीर उनका वै किर डुहराना घाटता हूं। पहली बात तो वजरीबा — नचीबाबाद रेसवे नाइन [श्री ग्रब्दुत लतीफ]

के बारे में है। मैंने म्नजं किया या कि इस लाइन पर पहले देहरा एक्सप्रेस चलती थी लेकिन बाद में उसको बन्द कर दिया गया था। इस को फिर चलाया जाए।

12.29 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

उसके बाद मैंने भौर श्री भक्त दर्शन जी ने जाकर डिप्टी मिनिस्टर साहिब से इसके बारे में गुफ्तगू की भौर डिप्टी मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि वह उस ट्रेन को जरूर चलायेंगे । उसके बाद पोलिटिकल कान्फ़ोंस में यह बात भ्राई थी भौर डिप्टी मिनिस्टर साहब ने जलसे-म्राम में एलान किया था कि यह ट्रेन चलेगी । लेकिन इस बक्त तक उसकी तरफ कोई तवज्जह नही दी गई है।

जो ट्रेनें इस लाइन पर चल रही हैं उनकी खराब हालन की तरफ़, स्रौर उनके डिब्बों की हालत की तरफ़ तवज्जह दिलाई थी। मैंने सर्ज किया था कि बह रेलवे ट्रेन नहीं है थल्कि छकड़े हैं। उसके स्रन्दर बैठकर इन्सान घूमना है, उसका सर घूमना है स्रौर हिलता है। मैंने खुसूसन फ़स्ट क्लास के डिब्बों की तरफ़ नवज्जह दिलाई थी, लेकिन साज तक वह डिख्बे प्रपनी जगह पर मौजूद हैं, उन में कोई रद्दोबदल नहीं की गई है।

भी जुझबक्त राय (खेरी) कंट गाड़ी कहिये ।

उपाष्पक महौदाः : एक वक्त में एक ही तकरीर हो सकती है ।

की प्रव्युत सतीक : मैंने यह ग्रर्च किया था कि स्टेशनों पर उबिया गोक्त का इन्तजाम किया जाय, क्योंकि मुसलमान मुसा-फ़िरों को बहुत तक्लीफ़ होती है, लेकिन ग्राज तक इसका कोई इन्तजाम नहीं किया ज्या मैंने ग्रर्ज किया था कि स्टेशनों पर बाध का

निहायत नाकिस इन्तजाम है। वह भी भपनी जगह पर कायम है। भ्रलबत्ता एक काम जरूर हम्रा कि उस चाय की कीमत एक म्राना भौर बढ गई । कीमत बढ गई. लेकिन चाय ग्रपनी जगह पर नाकिस ही है मैं ग्रजं करना चाहता हं कि जब मुसलसल दो सालों से एक चीज की तरफ़ **ग्रापकी** सवज्जह दिलाई जा रही है तो क्या हमारी तकरीरें इसी काबिल हंती हैं कि यहां से जाने के बाद उनको रही की टोकरी में छोड दिया जाये। कम से कम इतना तो होना ही चाहिये कि जब तकरीरें हों तो भ्राप हम को यह इत्तला दें कि फलां मतालबा जो हम ने रक्खा वह ग्रापको मंजुर है, ग्रौर फलां बनालबा इस बनियाद पर मंजर नहीं हो सकता है। कई मर्तबा खद डिप्टी मिनिस्टर माहब से मेरी श्रौर भक्त दर्शन साहब की मलाकात हई, जलसा श्राम नजीबाबाद पोलिटिकल काफ़ेंस में ऐलान हम्रा, लेकिन सब कूछ बेकार रहा। इसी लोइन पर जो प्लेटफार्म्स हैं उन के मताल्लिक दर्श्वारत की थी कि उनको उभारा जाये क्योंकि **धौ**रतों धौर बच्चों को चढने में बेइन्तहा तकलीफ़ होती है । लेकिन इस तरफ़ भी कोई तवज्जह नहीं दी गई । मैंने डिप्टी मिनिस्टर साहब से दरूव स्ति की थी कि वह कम से कम उस रास्ते ने गुजार तो जायें जिससे कि ग्रापका माल्म हो कि जो कुछ मैं मर्ज कर रहा हं उस में कितनी सचाई है। डिप्टी मिनिस्टर साहब ने मझेसे वायदा भी किया या कि वह जायेंगे, लेकिन भाज तक वह वहां तशरीफ नहीं लेगये। भलवत्ता हमारे श्री प्रकाश बीर शास्त्री एम० पी० वहां गये भौर परसों की अपनी तकरीर में उन्होंने इस लाइन के मतालिक आपके सामने अर्ज किया था । मैं प्रापसे धर्ण करना बाहता हूं कि हम रिप्रजेन्ट करते हैं भपनी कांस्टिटएन्सी को इसलिए लोग हम से मतालबा करते हैं। चमी भन्द दिनों का बाकवा है, मैंने एक

4197 Demands

जगह पर रेलव की तरक्की का तजकिरा किया भौर बड़े धच्छे झल्फ़ाज में किया, तो एक साहब ने बड़ी संजीदगी से कहा : जंगल में मोर नाचा , किस ने देखा । मुमकिन है हिन्दुस्तान में तरक्की हुई हो, लेकिन जिला बिजनौर की जो हालत है बह तो वैसी ही है ।

एक मा⊰नीय सदस्य : विजनौर के तो एक मिनिस्टर साहब भी हैं ।

श्वी प्रब्सुल लतीफ : मिनिस्टर भी है प्रोर हमारे डिप्टी निनिस्टर साहब का वास्ता भी उस जिले से है. वह वहां शिकार को वहां जाते हैं । यह दरल्वास्त मैं ने ग्राप के सामने फिर पेश की हैं । मैं यहां पर कोई लम्बी चौड़ी तरकरीर करने के लिये नहीं प्राया हूं, मैं तो सिर्फ़ कुछ शिकव गिले करने के लिये ग्राया हूं । मैं कम से कम यह जरूर महसूम करता हूं कि जो कुछ मैं ने यहां पर प्राप के सामने ग्रर्ज किया था,ग्राप में न कह कर जनरल मैंनेजर को कहता तो मुमकिन या कि काम हो जाता ।

एक मा.ने.स. सबस्य : ग्राप ने यही तो गल्नी की ।

भी झम्बुस सतीक: मैं यह मर्ज करना चाहता हूं कि अमेहडा गजरौला लाइन पर एक पुलिस थाना है । यहां पर बुनकर रहते हैं भौर वे कपड़े बुनते हैं । इस जगह के झास पास भी बहुत बुनकर रहते हैं जो कि कपड़े बुनते हैं भौर बाहर को ले जाते हैं। इस स्टेशन पर हमेशा से गाड़ी रुकती झायी थी, यह मैं ने डिप्टी मिनिस्टर साहब से भर्ज किया था भौर उन्होंने इस को नोट भी कर लिया था। लेकिन झाज बह गाड़ी बहां नहीं रुकती है भौर लोगों को बहत तकलीफ होती है।

धाखिर में फिर मेरी दर्क्यान्त है कि धाप एक नई गाडी, चाहे वह पसेन्त्र हो 2134 (Ai) L.S.D.—5 या एक्स्प्रैस, जरूर चलाये मौर जो तीन गाड़ियां इस वक्त चलती हैं उन में भ्रामद रफ्त बहुत रहती है, इम लिये कम से कम इतनी सहूलियत हो जाय कि हर ट्रेन में दो डब्वे थर्ड क्लास के भौर एक डिब्बा फ़र्स्ट क्लास का नजीबाबाद से दिल्ली के लिए भ्रटेच हो जाय ताकि गजरौला पर तब्दील करने में लोगों को जहमत न हो । मुबह की गाड़ी में एक थर्ड क्लाम का डिब्बा रहता है, बाकी को दो गाड़ियों में नहीं रहने । जब तक भ्राप नई गाड़ी नहीं चलाते तब तक इन तीन गाड़ियों मे दो डिब्बे थर्ड क्लास के भीर एक डब्बा फर्स्ट क्लाम का भटैच कर दिया जाय ताकि वहां के रहने वाले भ्रासानी से दिल्ली भ्रा सकें ।

For Grants

(Railways)

मुझ करं इतना ही मर्ज करना था। आग की रेलवे ने जो तरवकी की है, उन से कोई इनकार नहीं कर सकता। हो, हमारे कहने पर जरूर तवण्जह दी जाय, एमान हो कि इम लोग कुछ माप के सागने म्राजं करें वह माप रही की टोकरी में डाल दे।

[متحترم ا-بهیکر ماحب (بجلور)-پیشتر اس کے کہ میں اپلی تترر کا آغاز کروں متجور ایک بات بڑے افسوس کے ساتھہ کہلی پرتی ہے - میں مسلسل دو سال ہے اس معاملے کو لے کر تتریز کر رہا ہوں لیکن میدے کسی ای² کو رہا ہوں لیکن میدے کسی ای² مطالعے کو اس وقت تک نہ تو ملطور کیا گیا ہے اور نہ بی مجھکو اطلاع دیکٹی کہ اس کا کیا حشر ہوا - میں نے ایلن نتریزوں میں ڈیٹی میں اور ان صاحب اور مذسلار ماحب کی توجہ چلد چیزوں کی طرف دلائی تھی اور ان

4198

[شری عبدل لطیف] بات تو گجرولا - نجیب آباد ریلوے لائن کے بارے میں فے - میں نے عرض کیا تھا کہ اس لائن پر پہلے دیہرا ایکسپریس جاتی قہی لیکن بعد میں اسکو بلام کر دیا گیا تھا - اس کو پھر چلایا جائے -12:20 hrs

[MR DEPUTY-SPEAKER in the Chair] اسکےبعد میں نے ارر شری بھگت درشن جی نے ڈیڈی ملسٹر صاحب سے اس کے بارے میں گفتگو کی اور ڈیڈی ملسٹر ماحب نے عمارے ساتھہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس ٹرین کو ضرور چلائیں گے - اس نے بعد پولیٹیکل کاند,نس میں یہ بات نے بعد پولیٹیکل کاند,نس میں یہ بات ملسٹر صاحب نے جلسہ عام میں املان کیا تھا کہ یہ ڈرین جلے کی - لیکن اس وقت تک اس کی طرف کرئی ترجہ نہیں دی گئی ہے -

اموقت جو ترینیوں اس لائن پر چل رعی هوں ان کی خراب حالت کی طرف - اور ان نے ذہوں کی حالت کی طرف توجه دلائی تھی - میں نے مرض کیا تھا کہ وہ ریلوے ٹرین نہیں ھر بلکہ جہگزا ھے - اس کے اندر بیڈی کر انسان گھومتا رعتا ھے - اخبار نہیں پڑھ سکتا - میں نے خصوماً فرست پڑھ سکتا - میں نے خصوماً فرست پڑھ سکتا - میں نے خصوماً فرست پڑھ موجود ھیں - لائن میں کوئی ردو پر موجود ھیں - لائن میں کوئی ردو

<u>شوں خوشوقت رائم</u> (کھیوی): ارن**ت** اع ہی کہلے - اُپادھیکھن مہودے - ایالہ وقت میں ایک ھی تعریر ھو سکتی ھے -

شرى عبدال لطيف - ميں لے يہ <mark>مرض کیا تها که استیشنو</mark>ں پر زبیته گوشت کا انتظام کیا جائے - زکیونکہ با اس کے کم سے کم مسلمان۔ مسافروں کو بہت تکلیف ہوتی ہے - لیکن آج تک **اس** کا کوئی انتظام نہیں کہا گیا - میں نے عرض کیا تھا کہ اسٹیشلوں پر چائے كا ديايت ناقص انتظام ه_ود بهي ايدي جمله پر قائم ہے - المته ایک کام ضرور هوا که اس چانے کی قیمت ایک آنه ہوھ گئی - قیمت بوم گئی لیکن چانے اپنی جگه پر ناقص هی هے - میں عرض کرنا چاهتا هون که جب مسلسل د و سالوں ہے ایک چیز کی طرف آپ کی توجه دلائی (جا رہی ہے تو کیا هباری تقریریں (سی ٹاہل عوثی هیں که یہاں سے جانے کے بعد ان کو ردی کی ٹوکری میں چھرو دیا جائے - کم سے کم اتدا تو هونا هي چاهئے که جب کوئي تقریر هو تو آپ هم کو یه اطلاع دین که فلان مطالبه جو هم <u>ن</u>ے رکها۔ وہ آپ کو ملظور ہے - اور فلان مطالبه اس۔ بلیاد پر منظور نہیں ہو حکا ہے۔ کئی مردبه خود دیتی منستر ماهب ہے میری اور بهکت دوهن ماهب کی ملاقا هوئی - جلسه عام تهمهمایاد يوليقيكل كاندرنس مهن أعلن هوا ليكن سب کچه بیکر ره' - اس الن پر جو پلیمت فارم ھیں ان کے متعلق

شکار کو جائے تھیں - یہ درخواست جو میں نے آپ کے ساملے پھر پیش کی تقریر ھیں یہاں پر کوئی لسبی ہوری تقریر کرنے کے لئے نہیں آیا تھوں - میں تو مرف کتچھ شکوے گلے کرنے کے لئے آیا موں - میں کم ہے کم ضرور متحسوس کوتا ہوں کہ جو کتچھ میں نے یہاں پر آپ کے الملے عرفی کہا تھا - آپ سے نہ دہا ہوتا باکم جلرل میلیجر صاحب کو اپررچ کوتا تو ممکن تھا یہ سب کار ہوجانا -

ایک مافلیہ سدسیہ - آپ نے تو ______ فلطی کی -

آخر مهن پهر مهری درخواست هـ که آپ ایک نگی کاتی - چاهے وہ پسلتجر هو یا ایکسهریس ضاور چالهی - اور جو تهن کاریان اموقت چلقی ههن ان

درخواست کی تھی کہ ان کو اوبھارا جائے کہونکہ مورتوں اور بچوں کو چرعلے میں بے انتہا نکلیف ہوئی ہے - لیکن اس طرف بهی کوئی توجه نهیں۔ دی کئی - میں 🚊 ڈیٹی منسٹر حاجب سے درخواہ ہے کی تھی کہ رہ کم سے کم اس راستہ سے گزر تو جائیں جس سے کہ آ پ کو معلوم هو که جو کچه میں عرض کر رہا ہیں اس مہن کتنی سچائے ہے۔ دیتی منسلر صاحب نے مجھ سے رعدہ بھی کیا تھا کہ وہ جائیں کے لیکن آج تک وہ وہاں تشریف نہیں لے گئے -البقه شرى پركاش وير شاستنى ايم پى وهان کلے اور پرمون کی اپنی تقریر مہن انہوں نے اس لانن کے متعلق آپ کے ساملے عرض کہا تھا - میں آپ سے عرض کرنا چاهتا هون که هم (رېريزيلت کرتے ھیں اپنی کانسٹیٹیوھن کو اس لگے لوگ ھم سے مطالبہ کرتے ھیں -ابھی جلد دنوں کا واقعہ ہے - میں نے ایک جگه پر ریلوے کی ترقی کا تذکرہ کہا اور ہوتے اچھے الفاظ میں کہا - تو ایک ماحب نے بوی سلجیدگی ہے کہا - جلکل میں مور تاجا کس <u>نے</u> دیکھا - منکی ہے مقدرستان کے اندر ترقى هولى هو - ليكن ضلع ابتجلور کی جو حالت ہے وہ ریسی ھی ھے -ایک مالیہ سدسیہ - بنجلور کے تو ایک منسلر ماحب بھی ھیں -شرى عبدل الطيف - السلار بهي **میں م**نارے ڈیٹی منس<mark>ٹر</mark> ماجب کا

یہی واسطہ اس ضلع ہے ہے - وہ وہاں

[شری عبدللطیف] ۲ م آمد و رفت بہت رهتی ھے - اس لئے کم سے کم انلی سہولیت ہو جائے کہ هر ترین میں دو ذیہ تهرۃ کلاس کے اور ایک ذبہ فرست کلاس کا نجیب آباد سے دعلی کے لئے اتیچ عو جائے تاکہ سے دعلی کے لئے اتیچ عو جائے تاکہ میں لوگوں کو زحمت نہ عو - مبع کی گاری میں زحمت نہ کاری نہیں جلائے جب کلاس کے اور ایک ذبہ فرست کلاس کا اتیچ کر دیا جائے تاکہ وعال کے رهلے والے آسانی سے دعلی آ سکیں -

منجه کو اتقا هی۔ عرض کریا۔ نہا ۔ آپ کی ریلوے نے جو: رنی کی ہے۔ -اس ہے کوئی انکار نہیں۔ کر سکتا۔ -هاں - عبارے کہلے پر ضرور توجه دی جائے - ایسا نہ هو کہ هم لوگ جو کنچھ آپ نے ساملے عراق کریں۔ وہ آپ ردی کی توکری میں ڌالدیں -]

भी समराभ सिंह : (फिरांजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, कई सालों से सदन में एक मांग की जाती है कि रेलव बोर्ड का दफ्तर जो लगातार बढ़ता जा रहा है, रेलवे मंत्रालय का उधर जाना चाहिय । मैं मानता हूं कि शायद रेलव मंत्री यह जवाब दे कि चूंकि काम बढ़ रहा। है इस लिये रेलवे बोर्ड में झौर बहुत से झफसरो का मुकर्रर किया जा रहा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो काम बढ़ रहा है उस से जितना सोचने का काम है, नीति बनाने का काम है, उस नीति को सोचने में कौन मा काम बढ़ता है। इस बारे में यदि रेलवे मंत्री कुछ सफ ई दे सकें तो त्रच्छ; होगा। मैं इस में नहीं जाना चाहता कि इस माल रेलवे की धाम नी पिछले साल से ज्यादा है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले चार पांच मालों का वजट प्रगर देखा जाये रेलवे वोर्ड का, तो इस में हर माल बढ़ती दिखाई देगी। इस के बावजूद कहा जाना है कि हम मितव्ययना बतना चाहते है। इम लरफ रेलव मंत्री को जरूर ध्यान देना चाहिय।

अभी प्रध्नों के घंटे में कहा गया और पिछले पन्द्रह बीस दिनों से लगातार मल्क में यह चर्चा होती रही है, सदन में भी हई है, कि रेलवे इस कत्तंव्य का पालन करते में ग्रनमर्थ रही है कि जो कोपला खानों पर पडा तम्रा है खदा तमा, उसे इंडम्ट्रीज मर्थात उद्योगों को दे गके या घरों में पहुंचा मके। बार-बार सदन में यह बात कही जाती है। रेलवे मंत्री कहते है कि इन में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमको जितना लक्ष्य बनाया गया था दोनी पचवर्षीय योजनामी के ग्रन्तगंत, हम ने उसे पूरा कर दिया, **धी**र इस्पान भीर इंधन भंत्री कहते हैं कि उनका लक्ष्य जितना था उतना ही उन्होंने पूरा किया है, उस मे ज्यादा नहीं । मेरी समझ में नहीं भाता कि मखिर गलती कहां । मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन यदि प्त्रींनग कमिशन की गलती रही हो तो उन्होंने सही ढंग से योजना निर्मित नहीं की, भौर भव जो कुछ हो रहा है उस से मुल्क में उत्पादन में कमी हो रही है, जिस से कि मुल्क के लोगों को परेशानी हो रही है। कोयला की कीमतें जगह जगह बहुत बढ़ी हई हैं, इस को ध्यान में रसते हुए कम से

for Grants (Railways)

कम तृतीय पंच वर्षीय योजना के उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए वैंगन्स की जो स्थिति है उस को सही ढंग से ठीक करने की कोशि। जाय । यदि म्राप के श्रायोजक यह भी नहीं देख सकते कि जो योजना बन रही है और मुल्क में जो टक्तालोजी की उन्नति हो रही है, दूसरे क्षेत्रों में जो उन्नति हो रही है, उस से कितना उत्पादन बढेगा भ्रौर कितना कोयला इस्तेमाल करने की जरूरत पडेगी, तो यह किसी तरह की प्लेनिंग नहीं है। इस सन्दर्भ में ततीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत जो कुछ रेलों के विकास की व्यवस्था की गई है, मैं समझता ह कि वह भी झापका पूरा सामान झौर या त्रियों को ले जाने में ग्रसमर्थ होगी । इसलिय ग्रब समय है कि इसी वक्त से इस पर विचार किया जाय भ्रोर देखा जाय कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना के झन्तगंत कभी भी इस तरह की कोई दिववन न ग्राय जिसमें माल एक जगह से दूसरी जगह न जा रुके।

इस सन्दर्भ में प्रश्न आता है कि जो झापका रोलिंग स्टाक है उसके सम्बन्ध में सरकार की म्रोर रेलवे मन्त्रालय की क्या नीति है। बेगन्स के बारे में कहा जाता है कि हमारे पास कमी है। झाज से वई साल पहले से वैगन्म बनाय जाने चाहियें थे। वर्कमाप से काम लिया जा सकता था, लेकिन नहीं लिया गया । बयो नहीं लिया गया, इस पर प्रकाश पड़ना चाहिये। भाज से कई साल पहले हम सोच मकते वे कि जो लोकोमोटिवज हम बाहर से मंगाते हैं डीजल मौर एलेक्ट्रिक के उनके बारे में क्या किया जाय । एसे क्टिक के बारे में कहा जा सकता था कि हम उनको नहीं बना सकते, लेशित डीजल लोकोमांटिय्ज के बारे में हमने पहले से योजना क्यों नहीं बनाई ताकि उनका उत्पादन मरूक में हो सके । इस संदर्भ में जब हम देखते हैं कि धमरीका से हम डी. एस० एफ लोन मिलता है रेनों के पूर्नानमान के लिय भौर बिकास के लिय तो हम को सोचना चाहिये कि हम वहां से जो मोको-

मोटिव्ज खरीदते हैं डीजल के उस में वह मतर्कता बरती जा रही है या नहीं जो कि बग्ती जानी चाहिय । अभी पिछले दिनों लोकोमोटिब्ज खरीदने के सम्बन्ध में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि वैसे तो लोकोमोटिव्स की खरीद के लिए ग्लोबल टैंडर्स मांगे जाते हैं लेकिन डी० एल० एफ० लोन की यह च कि शर्त थी कि केवल ग्रमरीका मे ही इस रुपए से लोकोमोटिव खरीदे जाय, इसलिए अमरीका से ही टेंडर मांगे गए । ग्रमरीका में तीन फर्म लोकोमोटिव बनाती हैं. लेकिन जो उत्तर दिया गया उससे पता चल्ता है कि ज्यादा कीमत वाले टैंडर को मंजुर किया गया और कम कीमत वाले टेंडर को मजूर नहीं किया गया । मैं उसकी विभव-ताओं में नहीं जाना चाहता । हो सकता है कि रेलवे मन्त्रालय यह जवाब दे कि कम कीमत ताले टैंडर के लोकोमोटिव में कुछ खराबी थी जो कि दूसरे में नहीं थी। मैं मानता ह विः डी० एल० एक० लोन की यह धर्न है कि उससे हम दुनिया के बाजार से लोको-माटिय नहीं खरीद सकते, हमको भमरीका के बाजार से ही खरीदने होंग, लेकिन अम-रीका में भी जिसका टेंडर कम कीमत का है उसको मंजर न करना भौर जिसका ज्यादा कीमत का है उसको भंजूर करना में समझता ह कि यह उचित नहीं है। मैं चाहुंगा कि मन्त्री महोदय इस झोर ध्यान दें क्योंकि भविष्य में हमें झौर बीजे भी खरीदनी होंगी। तौर ग्राम पर यह चर्चा होती है कि इन बातों में कुछ गड़बड़ होती है। मैं नहीं कह सकता कि इसमें कोई झाधार है या नहीं, लेकिन जब कम कीमत का टेंडर मंजुर नहीं किया जाता भीर ज्यादा कीमत बाला मंजूर किया जाता हे तो इम प्रकार की शंकाएँ पैदा होने की गंजाइय होती है। मैं चाहुंगा कि इस प्रकार की शंकामां को दूर करने की जरूर कोशिश की जाए ।

इस सदन में केटरिंग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और बेंडिंग का जिक किया [श्री बजराज सिंह]

गया है। इस सम्बन्ध में रेलवे मन्त्रालय की एक कमेटी बी थी ग्रीर उसने कुछ नीति निर्धारित की थी उस पर चलने की रेल मन्त्रा-लय सोचता था. लेकिन ग्रफसोस है कि ग्रब उस नीति पर भी नहीं, चला जा रहा है। जहां तक केटरिंग का सम्बन्ध है केवल खोने पीने की चीजों का श्राप डिपार्टमेंटलाइजेशन करते है. सिर्फ बेचने की चीजों का विभागी-करण करते हैं। इससे लोगों के दिमाग में यह बात पैदा हो ही है कि शायद ग्राप कहीं होटल खोलने जा रहे हैं। इन विचारों से उन लोगों की बात को बल मिलता है जो राष्ट्रीयकरण नहीं चाहते । जब से ग्रापने केटरिंग ग्रपने हाथ में लिया है तब से जनता को चीजें खराब मिलने लगी है । म्राप देखेंगे कि इन बातों से जनता के दिमाग में राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध भावना पदा होती है। मैं तो चाहता हं कि मुल्क में जल्दी से जल्दी समाजवाद कायम किया जाए । लेकिन अगर समाजवाद के नाम पर एसी बातें होंगी तो लोगों के मन में राष्ट्रीयकरण के प्रति दुर्भावना पैदा होगी जो कि उचित नहीं है । मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हं कि हमते जो केटरिंग स्टेशनों पर भपने हाथ में लिया है उससे एक तरफ तो नुकसान हो रहा है श्रीर उसी के साथ साथ हमको भ्रच्छा खाना नहीं मिलता । भ्रापकी सरविस मच्छी नहीं होती । बासी खाना दिया जाता है। यह सारी चीजें हो रही हैं भौर रेलवे मन्त्रालय इस दिशा में कूछ नहीं कर रहा है ।

Shri Sonavane (Sholapur-Reserved-Sech, Castes): That is not correct.

Shri M. B. Thakore: (Patan): That is correct.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order; the hon. Member may be allowed to go on.

वी समराभा सिंहः कोई देखना चाहेतो इस चीज को देख सकता है। उस तरफ से माताज मापी कि ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि रेलवे मन्त्रालय एक बात के लिए तैयार हो जाए कि इन चीजों को देखने के लिए ग्रौर इनकी जांच पड़ताल करने के लिए एक पालियामेंटरी कमेटी, स्टेंडिंग कमेटी, बनाए जो रेलवे की सब चीजों की जांच पड़ताल करे। लेकिन केटरिंग के बारे में तो मैं चाहता हूं कि खास तौर पर जांच पड़ताल की जाए।

में जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की एक कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि जब्लिक घंडरटेकिंग की जांच पड़ताल के लिए एक स्टेंडिंग कमेटी होनी चाहिए । रेलवे विभाग तो एक बहुन बड़ा घंडरटेकिंग है, इसमें हजारों करोड़ों का लेन देन होता है । में चाहूंगा कि रेलवे मन्त्रालय इस बात पर विचार करे कि रेलवे के फाइनेंस, चल स्टाक ग्रादि दूसरी ग्रीर चीजों की भी जांच पड़नाल करने के लिये एक स्टेंडिंग कमेटी इस पालियामेंट के मेम्बरों की बनायी जाए जो कि इन चीजो पर ध्यान दे सके ।

तो में केटरिंग के बारे में कह रहा था। मैं चाहता हूं कि यह देखा जाए कि केटरिंग में किम प्रकार उन्नति की जा सकती है। यह सिर्फ प्रपर क्लाम के लोगो की सुविधा के लिए ही नही होना चाहिए। थडं क्लाम के मुम फिरों की मुविधाओं का भी पूरा घ्यान रखना चाहिए क्योंकि रेलवे की ज्यादातर मामदनी उनसे ही होती है। इससे केवल भपर क्लास वालो को ही फायदा न हो। इस पर रेलवे मन्त्रालय को पुनः विचार करने की जरूरत है।

सरकार की यह नीति रही है कि जो लाइनें लड़ाई के जमाने में उखाड़ ली गयी थी उनको फिर से लगा दिय आए घौर देश में ऐसी घांघकांश लाइनें फिर से लगा दी गयी हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि घागरा जिला में एक लाइन थी घागरा से बाह तक, जो कि ४०-४५ मील लम्बी लाइन थी, घौर जिसको लड़ाई के जमाने में उखाड़ लिया गया बा, उनकी म्रोर क्यों घ्यान नहीं दिया जा रहा है। म्रापकी यह नीति है कि देश मे जिन लाइनों का लड़ाई के जमाने में उखाड़ा गया बा उनको फिर से लगा दिया जाए म्रौर म्रापने ऐसी लाइनों को लगाने की कोशिश भी की है। मैं चाहुंगा कि इम लाइन को भी फिर से लगाने पर विचार किया जाए।

दुर्घटनाधों के बारे में सदन में चर्चा हुई है। अभी हमने रेलवे की लापरवाही के कारण देश का एक बहुन बड़ा पत्रकार खो दिया। परसों तरसों एक दुर्घटना में १३-१४ आदमियों की जानें गई हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देखते थे कि दुर्घटनायें नहीं हो रही थीं लेकिन अब फिर उनकी लहर सी आ रही है। मैं चाहूंगा कि रेलबे मन्त्रालय इम तरफ विशेप तौर से ध्यान दे ताकि इम प्रकार की दुर्घटनायें भविष्य में न होने पावे।

मै एक निवेदन करना चाहता हू इले-क्ट्रिफिकेशन के बारे में । ग्रापने हाल में मुगलसराप ग्रीर हावड़ा के बीच में इलेक्ट्रि-फिकेशन किया है जहां पर कोयले का क्षेत्र भी है। जो लाइनें कोयला क्षेत्र स दूर हैं उनमें कभी कभी एसी स्थिति हो जाती है कि वे बन्द हो रही हैं । इसलिये ग्रगर ग्रापको इलेक्ट्रिफिकेशन करना है तो ऐस स्थानों में करना चाहिये जैसे कि पंजाब, महाराष्ट्र ग्रीर गुजरान जा कि कोयला क्षेत्र स बहुत दूर है ।

Shri M. B. Thakore: There are no lines; what to talk of Electrification'.

भी तजराज सिंह : मै चाहूंगा कि भविष्य में यह नीति मपभाषी जाए कि उन स्थ नों में पहले इलेक्ट्रिफ्रिकेशन किया जाए जो कि कोचला क्षेत्र से दूर हैं प्रौर जहां कोयला पहुंचाने में दिक्कत होती है ताकि वहां के लोबों को कोयले की कमी के कारज कठिनाई का सामना न करण। थई।

को बक्सं, मैचीनरी भीर रोर्लिंग स्टाक प्रोग्राम हम को दिया गया है उसरे पालम होता है कि खोटी छोटी चीजों के निर्माण के लिए डेढ डेढ झीर दो दो लाख रुपया रखा गया है। मैं समझताहं कि यह देखना चाहिये कि इतना रुपया किस प्रकार खर्च होता है। उदाहरण के लिए माप देखें कि टंडला के स्टेशन पर एक भोवर क्रिज के लिए एक लाख रुपया रखा गय। है । इतना रुपया इस पर कैसे खर्च हो सकता है यह मेरी समझ में नही भाता। मैं समझता हं कि जितना रुपया हम चार्च के लिए रख रहे हैं उतना खर्च नहीं होता । इसमें कुछ न कुछ गडबडी जरूर है। मैं चाहंगा वि, रेलवे मन्त्री इस पर ध्यान दें कि बाजार में चोजों की कीमतें देखते हुए ये काम कम रुपए में होने चाहियें । म्रापको तो सारा सामान उचित मुल्य पर मिलता है फिर **क्यों दूसरी जगह** में ज्यादा तेज चीजें बननी चाहियें यह देखा जाना चाहिये कि हमारा रुपया ठीक तरह से तो खर्च हो रहा है। बीच में कोई गढ़बड़ी तो नहीं है । मैं चाहंगा कि रेखबे मन्त्री जरूर इधर ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा पैसा झच्छे तरीके से खर्ब न हो रहा हां जैस कि होना चाहिए ।

ग्रस्त में मैं रेलवे के रालिंग स्टाक की गतिविधि ग्रौर स्पीड के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह मभी संस्तोयजनक नहीं है। यदि हम अपने बैगंस जो कि ब्रमारे पास हैं झौर जैसी हमारी पोजीघन है उममें किमी तरीके में भगर एक घंटे उनसे ग्रीर ग्रकधिक काम ले सकें तो बहत उन्नति हो सकती है में समझता हूं कि सब तरीको से भगर हम इन पर ध्यान दें तो मुझ्किल नहीं होगा । यदि हम झपने बैगस स एक घटे भाषि न समय काम ले सकने में समर्थ हो आयें तो माज हमारे देश में कोयले झौर दुमरे सामान को ढोने की जो समस्या है भौर मैंगंस की जो कमी भन्भव की जा रही है, उस की स्थिति काफी मुघर सकती है। मुझे अफसांस है कि वह नहीं हा पाया है। कभी कभी कहा बाता है कि ऐसा इमलिये नहीं हो रहा है क्योंकि उमारे पास कानून नहीं है ताकि

[श्री वजराज सिंह]

लोगो को मजबूर किया जा सके कि वे सामान जल्दी से उठाये ।

नई दिल्ली के बारे में कहा गया है। मै आपको विश्वास दिलाना चाहता हं कि यदि आप इससे सम्बन्धित कानन में कोई कडापन लाना चहते हैं तो अन्य अपना प्रयोजल लेकर इस सदन के सामने ब्राइये ग्नीर उसके लिए सबसे मदस पहले रजामन्द हो जायगा कि हमारी रेलवेज का चल स्टाक जल्दी जल्दी हिले जले । कानन का बहाना बना कर मुल्क का सामान एक जगह मे दूमरी दूसरी जगह न जा सके, तो यह उचित वात नहीं होगी । मैं चाहंगा कि हमारे रेलवे मन्त्री महोदय इस विषय में जर। गम्भीरता में जांच पड़ताल करायें ग्रौर स्वय देखे कि ग्राज हम चल स्टाक से जितना सामान लिये जा रहे हैं वह क्या सन्तोषप्रद है ग्रीर काया ग्रपने **वैगं**स से ए**क घं**टे रोज अधिक काम नहीं लिया जासकता है ? कहीं ऐसातो नहीं होता है कि वैगंस हमारे कही कहीं एक एक और दो. **दो दिन पड़े रहते हैं ? ग्रधिक काम लेने के लिए** यदि किसी कानून में परिवर्तन करने की जरूरत हो तो कानन में तबदीली कर लें। माज मुल्क की मावश्यकता इस बात की है कि देश मे जो भी उत्पादन हो रहा है, कच्चे माल भौर फिनिश्ड गुड्स का तमाम उत्पादित माल एक जगह से दूसरी जगह तेजी के साथ भौर समय के घ्रन्दर पहुंचे।

भभी चर्चा हो रही थी कि हम विदेशों को ४, ४ लाख टन चीनी भेजने वाले हैं। ४, ४ लाख टन चीनी को कारखानों से पोर्ट तक ले जाना है उसके लिए कम से कम ३०००० वैगंस चाहियें। इसी तरह स देश में कोयले का उत्पादन बढ़ रहा है जरूरी वात है कि जितने हमारे पास वैगंस हैं उनसे हम कम से कम एक घंटे ज्यादा काम से सकें। इसी तरीके से भपनी लाइस को कैपेसिटी को बढाने की कोशिश करें । रेलगाडियों की गतिः को बढाने की कोशिश करें ग्रीर १०, १४ मिनट का फी फर्क अगर हम डाल सकते हैं तो डालें। मझे बतलाया गया है कि जापान में रेलें बहत तेज दौड़ती हैं। मझे पता नहीं कि हिन्दूस्तान में इस स्पीड को बढाने की दिशा में कोई एक्सपेरीमेंट क्यों नहीं किया जाता । इस बान की जांच होनी चाहिये कि हिन्दुस्तान में हम ग्रपनी रेलगाडियों को क्या ग्रौर तेज नहीं चला सकते हैं । क्या हम अपनी गाडियों को फीक्वेसी नही बढा सकते हैं. दस. दम ग्रीर पन्द्रह, पन्द्रह मिनंट के बाद क्या हम अपनी पैसेंजर ट्रेंस और गडम देन नही छोड़ मकते हैं ? मैं समझता हं कि ग्रगर इस विषय में जांच पड़ताल की जाय ग्रौर उसके लिए कोशिश की जाय तो यह सब हो सकता है ग्रीर जरूर एक ऐसी स्थिति ग्रा सकती है जिसमें हम अपना माल ज्यादा और अधिक शीघता स ढो सके और अपने पैसेंजर्स को और ग्रधिक तादाद में ग्रौर तेजी के साथ एक जगह मे दसरी जगह पचा महंकें।

मुझे ग्रौर विशेष नहीं कहना है। मैं सिफं यही कहना चाहंगा कि हमारी रेलवेज को कर्मांधयल लाइन्स पर चलते हुए सेवा करनी चाहिए जैंस कि हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने जनता पर करों का भार बढ़ा दिया है हमारी रेलवेज को जनता पर टैक्स लगाने की जल्द-बाजी नहीं करनी चाहिए ग्रपिनु उसे तो एक कमर्षीयल सर्विस के तौर पर ग्रपना काम करते रहना चाहिए ।

Shri T. Subramanyam (Bellary): The railway₃ constitute our greatest national undertaking with a capitalat-charge of Rs. 1560 crores, and employing about 11,60,000 people. It purports to play the dual role of a public utility undertaking as well as a commercial enterprise.

We have various modes of transport in our country, the roadways,

the railways, the waterways, and the airways also. We must have a national policy of integrating all these modes of transport, if the needs of the growing economy and the development of our country have to be met satisfactorily and adequately. A committee has been appointed, which is known as the Neogy Committee, to recommend what properly should be the long-term transport policy of the country, so that the development of the transport machinery may serve the growing needs with economy and efficiency, and also the avoiding duplication, role of the various modes of transport in the coming five to ten years; also, the mechanism to regulate and control the various modes of transport and co-ordinate their activities has to be recommended by this committee. An interim report has been received, and I hope that Government will take speedy action with regard to this matter.

We have undertaken to build up the socio-economic welfare of over forty crores of people, and industrialisation is going on at a very speedy rate, but, unfortunately we find that the modes of transport are not able to cope up with the demands and the requirements. That has been our experience. Almost every day, in the Parliament, the question comes up that wagons are not available to lift up the coal. Even the Food and Agriculture Minister was complaining that adequate number of wagons were not available even to lift foodgrains from one place to another. This question has been coming up frequently before this House in connection with transport of steel, minerals etc. The railways have also been set the task of taking up greater and greater responsibilities in the Third Five Year Plan. Therefore, I urge that immediately, a decision should be taken with regard to co-ordinating the various modes of transport. At the same time, there should be a vigorous sort of search or introspection on the part of

the Railway Board to cope up with the needs of the developing economy.

In the Third Five Year Plan, the task has been set for the railways to lift 93,000 million ton-miles, and that will mean an incerase from the Second Plan target of 54,000 million ton-miles. The increase will be of of the order of nearly 39,000 million ton-miles. It is a huge task, almost double the work that was taken up in the Second Plan. I again urge the Railway Board and the Railway Ministry to have a vigorous search with regard to this matter.

In the Second Five Year Plan, for development of the railways. Rs. 1121.5 crores were invested. In the Third Plan, it is proposed tentatively that Rs. 1255 crores should The be invested. Second Plan targets with regard to the receipt of locomotives, coaching-stock and wagons, we are told, will be almost fulfilled. In the Second Plan, about 2100 locomotives, 8500 coachingstock, and about a lakh of wagons will be received by the end of this month. That is a matter for gratification. In the Third Plan, we are told that 1700 locomotives, 7800 coaching-stock and 110,000 wagons will be received. We are also told that we shall be attaining selfsufficiency with regard to the equipment of our railways.

In the Second Plan, 800 miles of new railway construction were undertaken. We are told that that also will be practically reached. This represents mainly the requirements of the steel and coal industries, and the operational requirements of the railways themselves. We are told that in the Third Plan also, the same programme will continue, and about 1100 miles of new railway construction will be undertaken.

In this context, I must say that there i_3 an acute feeling of dissatisfaction in South India, and I shall be failing in my duty, if I do not give expression to that sort of feeling. It

[Shri T. Subramanyam]

is a bad thing to allow that sort of feeling to continue. It is also a fact that in the Third Five Year Plan also, according to the proposals made, we do not have any railway constructions in South India.

The hon. Minister has said in his budget speech at page 13, that

"In the matter of construction of new lines the Planning Commission have so far allotted Rs. 120 crores. This will provide approximately 1160 miles, for representing lines essentially required either in connection with the Railways' operational needs in connection with the or industries and development of m.accal resources. The latter include 200 miles for development of new coal fields and about 50 miles for a new line to serve the proposed port at Haldia. The provision for new lines is being reviewed in consultation with the Planning Commission.".

That gives a little margin of hope for us. We are further informed:

"I am hopeful that it will be found possible to make a further allocation of funds, to meet the demands for new lines to be constructed on grounds of political, social and economic development in certain areas more particularly in the South."

That is a gratifying and heartening thing. The word 'political' also has been advisedly. I presume, because that feeling does exist. Of course, it is based on very justifiable and very solid grounds. No new railway construction has been undertaken; and after the reorganisation of States, aince 1956, there has been a very acute need for new lines being constructed. As you know, geographically, as we proceed towards Cape Comorin the land tapers, and the inter-links that have to be added would be very narrow, sometimes 40 miles, sometimes 50 miles and so on, and they will be not more than 100 miles generally. If these links are constructed, then the way will be opened for the development of industries, and for enterprise and for trade and commerce.

13 hrs.

I would like to mention the lines that should be taken up immediately in South India. We have been agitating for them since 1956; the demand has been insistent and it has to be satisfied. It is a case of must, I say. The lines are: Hasan-Mangalore, Kottur-Harihar, Ravaddug-Chitaldrug, Hubli-Karwar and Salem-Bangalore. Priority should be given to these lines. We do recognise that there is very great need to give priority for the defence of our country and for the development of iron and steel industry, as also for the operational requirements of the railways themselves. After satisfying these three requirements, I would urge the Government to take up these railway lines in South India and satisfying the insistent demands there. It has been recognised by the Planning Commission and I hope to a speedy Government will come decision with regard to this matter.

Then, Sir, I urge that one or two more trains should be introduced in that area. We are told that a number of passenger trains have been introduced from 1956-57. I hav been urging that a fast express train should be started from Bijapur to Bangalore via Gadag-Hospet-Bellary and Guntakal. From 1956 when the States **Reorganisation** came .n, Mysore has become a bigger State, the Karnatak State. More areas have come in and more people are going towards Bangalore. But for thirteen hours there is not a single train between Gadag and Bangalore on this line. There has been an agitation for a long time; the traffic is increasing enormously and the equipment of the railways has also increased. I have been agitating for the introduction of this train.

I would in this connection just quote a few figures. The number of new trains introduced in 1956-57 was 119 on the broad gauge and 43 on the metre gauge; in 1957-58 it was 118 new trains on the broad gauge and 27 on the metre gauge; in 1959-60 it was 165 new trains on the broad gauge and 25 on the metre gauge; in 1960-61 it was 58 new trains on the broad gauge and 18 on the metre gauge. In 1956 when I asked for the introduction of a new train, I was informed that when the position with regard to the availability of locomotives and rolling stock improved, this question would be considered. Hundreds of trains have been introduced in other areas. I do not know why it has not been possible for Government to introduce this on train, though there is very great need for it

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri T. Subramanyam: I will take only two more minutes.

After the reorganisation of States people coming from the Karnatak areas of Hyderabad, Bombay and from Bellary district have to go via Guntakal to Bangalore for various transactions and Government work. Many passengers coming from that area have not been able to find accommodation at Guntakal to proceed towards Bangalore. I suggest that some more carriages may be attached to the trains proceeding towards Bangalore.

Then, Sir. I was informed sometime back that an additional broad gauge line would be constructed between Guntakal and Hospet to enable iron ore to be exported to other countries. It is of the utmost importance. It fetches us a substantial amount of foreign exchange. The iron ore is of the richest variety and is in great demand in other countries. I, therefor urge that this line should be constructed as early as possible. Track renewals and strengthening of bridges have to be taken up on the Kottur-Hospet, Rayadrug-Bellary and Gadag-Sholapur and completed as early as possible.

I am glad there has been a reduction in the claims filed from year to year, but still Government had to pay Rs. 3:13 crores in 1958-59 and Rs. 3:74 crores in 1959-60. Lakhs of claims are being filed from year to year. I hope Government will take adequate steps to minimize this.

Mr. Deputy-Speaker: The grievances which ar_e being voiced are mostly local in character and hope that can be done within ten minutes. I would request hon. Members to condense their remarks so that a larger number of hon, Members may be accommodated. Naturally there is a desire this time on the part of many Members to speak.

Shri Kalika Singh (Azamgarh): Sir, the Railways are the biggest of the public utility undertakings in India and they are said to be the fourth largest network in the whole of the world. It is, therefore, the responsibility of the Government to see that they are run most efficienctly, more particularly because they are directly connected with the progress of our Five Year Plans. At the commencement of the first Five Year Plan it was thought that railways were not very essential; so no money was provided in the First Draft Outline which was presented to Parliament. Later on a sum of Rs 200 crores was provided; at the end of the Plan, however, it was found that a sum of Rs. 423 crores had actually been spent on the railways. So, the railways spent Rs. 200 over and above the amount allotted to them. So it was the progress of the Plan that showed that the Railways are very essential and the planners were wrong.

In the Second Five Year Plan, therefore, a sum of Rs. 1,125 crores had been provided for the railways. At the end of the Plan we see that the whole of this sum has been utilised,

[Shri Kalika Singh]

although the other Departments were not able to utilise the whole of the sum allotted to them. In the case of the railways only an amount of Rs. 4 crores remained unutilised; that is they spent Rs. 1,121 crores.

The Railways are very essential to meet the transport requirements of the country. The investment on this public utility undertaking is Rs. 1,732 crores. With this investment we should see that the railways are run very efficiently. We have also to see that the foreign aid available to the railways is more than to other public undertakings or developmental works. The World Bank has been from time to time advancing loans because the capital at charge is substantial and the railways have got a very big asset. The International Development Association has also come into being and I think more and more money will be available from that Association apart from the World Bank. With the amount allotted in the Third Five Year Plan, the railways would be able to complete their planned programme with the result that the transport requirements of foodgrains, coal, steel and other essential items would be met very efficiently.

There is one thing I have noticed. It is that the working expenses have gone very high. In 1938-39, the gross earnings were Rs. 107 crores and the working expenses Rs. 71 crores, but in 1958-59, the gross earnings rose to Rs. 392 crores and the working expenses to Rs. 324 crores. The increase in the gross earnings during this period was nearly 366 per cent, but that in the working expenses was 456 per cent. If the gross earnings increase, the working expenses should also increase, but not more than the rate of increase in the gross earnings. But as I have just now shown, the increase in working expenses has been 100 per cent more than the increase in gross earnings.

Then I have noticed that there is a b'g increase in the number of staff. The figures given in Indian Railways (1959-60). Table XVIII, show that in 1938-39, the number of Class I and II staff was 1,784, but in 1959-60, it rose to 4,408. As regards Class III(a) employees, that is, those employees who were receiving more than Rs. 250 per month, the number in 1938-39 was 7,602, but in 1959-60, it rose to 23,866. The strength of Class IV employees has not increased so much in Class IV, there are two entegories. (a) and (b). In category (a), the increase is from 98,000 to 1.81,319. These figures are for 1951-52 and 1959-60. In the (b) category, the figures for the same period are 4,92,856 and 5,09,653.

So the increase in Class IV employees might be taken to be 100 per cent or even less, but the increase in the case of Class I, II and III(a) is more than 400-500 per cent. So the working expenses have gone up very high and the pattern of employment also during these years shows that the higher class officers have increased in number more than the lower class of officers. The operational efficiency of the railways has to be judged by the performance of those persons who really work the lines on the spot. If there is an increase in their number, efficiency will certainly improve. But if we go on increasing the staff in the offices who do not actually operate the lines, that might not be so much conducive to the promotion of efficiency of railways. Therefore, it has to be discouraged.

As regards passenger earnings, the earnings from air-conditioned coaches in 1959-60 was Rs. 1.18 lakhs, from first-class Rs. 8.06 lakhs and third class Rs. 1,11,90 lakhs. Here also, we have to see that we provide more amenities to the third class passengers. But overcrowding has been going on and we have seen on railways, particularly in the metre gauge, that there is a lot of overcrowding especially when there is mela traffic. We just cannot bear the sight of a train in the metre gauge when there is mela traffic.

Shri M. B. Thakore: In the summer season also.

Shri Kalika Singh: People travel on the roof of the trains and accidents have taken place. Instead of providing more trains and more coaches on the lines, the authorities advise pilgrims not to travel. If people want to travel and visit places of pilgrimage, the railways should provide the necessary travel facilities rather than discourage them. I think the railways do not actually want people to stop travelling to pilgrim centres; they only want to avoid the responsibility that may be fastened on them when passengers fall down from trains or other accidents take place. Therefore, they only give a warning.

There is one more point, a very important one. This is concerning Moghalsarai. It is stated:

"The daily average illotments in the direction above Moghalsarai was 1,687 wagons compared to the previous year's figure of 1,661 and the movements reached a record figure in September 1959, when a daily average number of 2,002 wagons were moved through Moghalsarai compared with the previous year's record of 1,792 wagons".

Moghalsarai represents the biggest bottleneck in transport in the whole of India. Coal and other goods wagons passing through Moghalsarai Bengal-Bihar collieries. come from Now one alternative line is being provided. Garhwa-Robertsganj, to divert some of the wagons, but in view of the increasing number of wagons, it is stated that by the end of the Third Five Year Plan, the number of wagons that will be passing through this bottleneck might rise even up to 6,000. Then I think one alternative line,

for Grants 4222 (Railways)

will Garhwa-Robertsganj not he enough. So I propose that a bridge should be constructed at Ghazipur. This has already been examined by the railways. The Research Institute at Poona has also, I learn, reported that the bridge is feasible at that point. So the Ghazipur railway bridge should be constructed and the line from Dildarnagar to Nagsar should Dass over Ghazipur, and then it should pass from Azamgarh to Akbarpur or straight from Ghazipur to Zafrabad, which is only 60 miles. That will be a second alternative to transport all the coal wagons avoiding the Moghalsarai point.

I want to thank the Railway Ministry for o_{ne} thing. For two or three years we had been demanding that the track between Mau and Shahganj should be renewed. It has been there ever since 1907, and was not renewed. Now it is being renewed at a cost of Rs. 50 Jakhs. I have been told that now the trains there on the metre gauge will be running at a speed of more than 35 miles instead of at the present rate of 15 miles. For that I thank the Ministry.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Sir, this is discrimination.

Mr. Deputy-Speaker: I should have given perference to those whose tracks have not been renewed.

Shri D, C. Sharma: His track has been renewed.

Shri Aurobindo Ghosal (Uluberia): I had no intention of mentioning issues already discussed, but some of them are so pressing that they require emphasizing.

First, I will refer to catering, which has been already refered to by my hon friend Shri Braj Raj Singh. The quantity, quality and the price of the food supplied by the contractors ...

Shri M. B. Thakere: It is departmental now. Shri Aurobindo Ghosal: ...differs from station to station and from contractor to contractor. We know that some standard has been laid down, but in practice this differs. I request the hon. Minister to see if inspectors can be appointed to check the quality, quantity and the price of the meals that are supplied by the contractors.

As regards the meals supplied by the restaurant car of the railways, the price of the items is increasing daily, and it has almost reached a prohibitive limit. So, I request the hon. Minister to see if the profit element can be reduced on the meals supplied in the restaurant cars to passengers.

Regarding the three-tier system, most of the Members have pointed out the difficulties. I would like to suggest one thing. Previously, in the three-tier classes, they used to supply some chairs, one-seat chairs. These used to be left vacant on one side for the sitting of persons who do not like to sleep for some time at night, but these chairs have also been now converted into berths. What happens? During day time the passengers of the middle berths have got to sit on their seats with their luggages on their laps. Therefore, either you must retain the old system of providing chairs on one side, or at least you should keep the vacant for keeping upper berth luggage. This is my suggestion regarding the three-tier system.

Regarding the suburban trains of the South-Eastern Railway, in the last 20 years the passenger traffic has increased by about 400 per cent, but the trains have increased by only two. The total number of up and down sub-urban trains in 1940 was 46; in 1951 it was 44 and in 1959 it was 48, but during this time passenger traffic has increased by about 400 per cent.

Secondly, not only is there overcrowding, but the running time has been extended too much. The running time has been increased by about 50 per cent. Previously the 16 or 17 miles used to be covered in one hour by the local trains. Now it is being covered in one hour and 20 minutes. I would request the hon. Minister to see that the speed is increased and the running time of the local trains reduced on the suburban side of the South-Eastern Railway.

Now I come to the trade apprentices of Kharagpur. In Kharagpur, about three years ago several hundreds of these apprentices were trained, but only a few of them have been absorbed. Even today, about 200 trade apprentices and carriage apprentices who have received training at the cost of the railways have been kept unabsorbed. I do not think in any other zone of the railways, such skilled hands to whom training has been given at the cost of the railways are being kept unemployed. I would request the Minister to consider giving employment to these carriage and trade apprentices of Kharagpur.

Yesterday, a news item has appeared to the effect that in the North Eastern Frontier Railway, in 1959 about 200 young men were declared fit for getting work by the Railway Service Commission, but none of them has been absorbed yet. The difficulty is this, that the Employment Exchange also does not allow them to register their names, because they have been approved by the Railway Service Commission, but they are not getting absorbed in the railways either. So, that point also should be considered by the hon. Minister.

Another point to which I would like to refer, which is very important, is that the railway yards of Chitpur and Shalimar are being used as underground commodity markets. In the first week of February, it has appeared in the papers that the hoan. Deputy Minister, Shri S. V. Ramaswamy, visited the railway yards of New Delhi and found huge quantities of coal and firewood heaped there, and they were not released by the business men in order to create artificial scar4225

Demands

city in the market, because of the low whariage rate. What happens in Calcutta is this. All the rape seeds are sold from the Chitpur yard. About 35 lakhs maunds of mustard seed are imported mainly from Bihar and U.P. Daily, the Delhi market opens in the morning and the prices are fixed in Calcutta towards the afternoon. In the Chitpur yard the rape seed bags are kept in the wagons, they are not released. There, underground market is run in the yard on the railway receipt itself, and that is being allowed. The real market, the producers' market, is in Howrah, but the goods are to be taken delivery from the Chitpur yard. The sample of the goods which are shown in the market, in the Rail bazar of Howrah, are not the same or similar to those delivered from the Chitpur yard. This sort of corruption is being allowed, and in all the newspapers of West Bengal this has come out that underground share market is being run in the Chitpur railway yard and Shalimar godown. This should be checked. 28th February, 36 wagons of On mustard seed had arrived in Calcutta. but on that very day the price of mustard oil was increased by Rs. 20 a maund. It is inconceivable. In one the price of mustard oil was dav increased by Rs. 20 a maund, though on that very day 36 wagons had been received in Chitpur yard. That is because the share market is being allotted to be operated in the railway yard itself. It is being operated on railway receipt without releasing the goods. That has to be checked.

The other day it has come in the newspapers that there was a pitched battle between the Railway Protection Force and the people of the Railway Works Inspectorate in Shalimar, in which about seven persons have been seriously injured. The persons of the Railway Works Inspectorate were taking out goods from the railway precincts which was opposed by the Railway Protection Force, and there was a pitched battle between them. This is going on and the all

1882 (SAKA) for Grants 4226 (Railways)

the small engineering factories of Howrah are run by the snuggling of nailway goods. So many lorries have leen seized by the Police on the G.T. Road when the railway goods have been so taken away by these smugglers. Naturally, more care should be taken to check these corrupt things.

Then, I would like to mention about the D.S.T. staff-the District Signalling and Telecommunication Engineering staff. This office was in Garden Reach ever since 1936. After the strike, they were informed that this office would be transferred to Madhya Pradesh. When there was a row, it was changed and they were given the assurance that the office would not be shifted. But, again, hardly a month has passed, the office has been shifted Chakradharpur. Some of those to employees who were given an assurance by the previous officers that their services in any case shall not be transferred from Garden Reach to Chakratharpur have all of a sudden beed transferred to that place. I would like the hon. Minister to consider the cases of these persons

Then, I would like to refer to the case of railway employees. There has been much discussion on the necessity for high operational efficiency and many hon. Members have suggested co-ordination between the different Ministries in the matter of wagons and other things. But one point that: has been overlooked is that real operational efficiency depends upon the employees who keep the whole thing moving.

The hon. Minister in reply to the general discussion has assured us hat there would be no victimisation and that the cases of those 500 employees whose cases are still pending and who are still out of service will be corsidered favourably. Still, yesterday I have received ~ telegram that one of the Secretaries at Garden Reach has been victimised. Though that assurance has given by the Railway Minister, still there is victimisation.

[Shri Aurobindo Ghosal]

going on there in the Railways. Therefore, I would request the hon. Minister to see that further victimisation does not take place.

Next, there is the question of the Light Railways. It had been stated by the hon. Minister that as the agreement exists between the Distric' Board and the Light Railway it is not possible for them to nationalise the Railway. If that is so, I would ask, 'Is it the policy of Government to nationalise Railways or not?'. I would like the hon. Minister to consider this point.

There is the Howrah-Amta Light Railway which is run by Martin & "Co. If you do not want to take the responsibility of nationalising this Railway, then you should allow them to extend their services. The people of those areas have been demanding a line from Santragachi to Bistupur via Arambagh for the last 10 years. Government is refusing to accept that demand. Naturally, if you do not accept the responsibility of taking a new line, why do you not allow this Light Railway to do it-if they want to extend the line to those places via Munshirbat Penro.

We are being told that Government does not want that these Light Ra lways should exist and that they are not going to extend these operations. If they are not in a position to take these new lines to these places then let them give permission to the Light Railway to extend their railway line to those places where government is not willing to take new lines.

Lastly, I would refer to the case of the retired railway personnel, personnel who have already retired and who are entitled to get benefits with retrospective effect as their claims have already been admitted as just by the Railway Board. I would request the hon. Minister to sconsider these cases. F nally, I would congratulate the hon. Minister that he has been able to keep himself away from the contamination of the hon. Finance Minister who has imposed taxes on whatever is fomed in heaven and on earth in order to make our life a hell.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Sir, I would like to make only a few observations. The Railway success has to be judged, in my opinion, not so much by the amount of contribution it makes to the General Revenues as by the amount of facilities it gives for growing traffic in men and goods. Though the Railways are a commercial concern, the matter of concern is not only the profit it makes bu' the convenience of the entire Indian public who are also interested in it as taxpayers. So, there is a good deal of importance attaching to that aspect.

The other aspect of the Railways is that it is a source of developing the country. As a public utility concern also it is equally important. And, from that point of view, the scope which the Railways have been able to give to the trade and traffic in men and goods is also a matter which has to be counted as one of the criteria to judge the real success of the Railways.

Many of the hon. Members who have preceded me today and other days also in the general debate have pointed out the shortage of wagons everywhere. I also want to bring that point to your particular notice. In fact, the hon, Railway Minister, in his speech, also admitted that they are making great efforts to cope with the increasing traffic and yet they have not been able to give sufficient numbers of wagons to the trade which is growing now.

I have brought to the notice of the Rai!way Ministry the complaint about the shortage of wagons at particular stations, Nagpur and Itwari, on the complaint made by the timber merchants of those places. A question

was also tabled by me. Unfortunately, the question could not be accepted as a Starred Question because for the date on which I wanted the answer the whole list was full and so it was treated as an Unstarred Question. The reply that was given to me only stated that every effort is being made to step up loading to the maximum extent possible within the availability of wagons. It is not a bad reply; it is hopeful. I have nothing to say about the language of the reply. But that does not solve the difficulty of those who have complained.

I would draw attention particularly to the fact that the timber merchants have been complaining about the shortage of wagons at Itwari and Nagpur stations for the last 3 months. The total wagons required on 8th January, 1961 were 63. Further additions to the requirement for the period 9th January 1961 to 27th February, 1961 was 39. The total re-quirement was, therefore, 102. As against this, the number of wagons supplied prior to 31st December, 1960 is only 25. So, I am told that there is a great shortage of wagons. Wagons are yet to be allotted although indents for them is accepted in January. So, after making necessary additions and sub-tractions, the total number of wagons required against which indents are not being accepted is 66. This complaint has been there for nearly some months together. You can imagine what amount of loss it would mean to the timber merchants to allow their stock to lie there without being allowed to be sent to the proper destinations in proper time.

The Railways may have their own difficulties. But I want to say that the Railways must see to it that they invite traffic. If that is not done there are others who are doing itand they are our brethern too. But we will be losing a good deal of profit which ought to be earned by the Railways because. I attach great importance to the Railways particu-

2134(Ai) LSD-6.

for Grants (Railways)

larly for carrying heavy goods. If that capacity of the Railways is not improving there would be much cause for complaint by the people. I hope that this will be duly noticed by the Railway Department and something will be done to look into the grievances of the timber merchants. The association had been sending representation after representation to the Chief Operating Superintendent, Central Railway and copies of these are being duly supplied to the hon. Railway Minister.

Now, I want to bring to the notice of the Railway authorities the point which I have been thinking for many years. When I was here in the old Legislative Assembly, we tried to make some improvement of railway communications in Vidarbha and the Maharashtra part adjacent to Vidarbha. Among the improvements which we succeeded in making was the construction of a narrow-gauge line from Darwha to Pusad. Now, later War came, this on, when the first line was among those that were to be dismantled when this matter was brought to the notice of the authorities they said that they would not dismantled this line and if at all it had to be dismantled, it would be done after certain further facts were ascertained. But the line was removed without the notice of the railway authorities. These things will be found in the old records if the hon. Minister goes through them. I have got the old correspondence with me. But then a specific promise was given that when dismantled lines were taken up for restoration, this would be one of the first. After that fortunately circumstances changed and the War was over and new lines were taken up for construction. I was not here then but was lying ill at Poona. I sent telegrams to our hon. friend, Shri Lal Bahadur Shastri, who was for some time in charge of the Railways, about this line. Till lately the matter was under consideration and I have been recently told that the matter had been abandoned altogether. I put a specific

4230

[Dr. M. S. Aney]

question but that could not come up and so it was treated as an unstarred question and I found that the answer was that it was an unremunerative line. I want to ask this question. Are they relying upon some old records made by the old railway agent? Have they really made any new enquiries? I am in a position to prove that it is not only not unremunerative but it is more remunerative than many other lines sanctioned. They should not take it up as a matter which has been finally decided but should keep it under consideration till they find out the facts.

There is one more point. At that time among the lines that were sanctioned was the Khandwa-Hingoli line also. The survey was made and this line had come up but the line from Narkhed to Amravati was not taken up as the retrenchment policy came in and we find that the matter has been abandoned. Efforts should be made to look into the old records and they should find out whether it is not worthwhile to take up that line. The district through which it has to pass -Amravati-is one of the most fertile districts of Vidarbha. So, it will be a payng proposition.

There is one more suggestion and I shall conclude. Thousands of pilgrims go every year to Badri Narain and Kedar Nath. If there be hill stations, Government does not mind spending money for construction lines to those places and connecting them by railways.

The Deputy Minister of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): Their sanctity will be lost.

Dr. M. S. Aney: There are many people who thing that it is worthwhile going there and if they reach there, the sanctity, if lost will be restored. These are religious places, just like tourist places. They should be made attractive and accessible to people. Every Hindu believes that it is as meritorious to help a pilgrim to a holy shrine as to make the pilgrimage himself. If sins are made in laying the line, the sins will be washed away by a dip in the Ganges there. These are the principal matters. About other matters, I shall correspond with the Railway department.

Shri Naniappan (Nilgiris): Sir, I was pleased to note that the Railwary Minister announced on the floor of this House more than once that the railway line on the west coast which is needed will be laid. Sir, the west coast which is needed will be laid. Sir, the west coast is well-connected by sea, air and also by road. The national highways are laying a road on the west coast and the Railway Minister was very right in saying that there should be a railway line on the west coast. In fact, there is a metre gauge railway extending from Punjab in the north to Kerala in the south. Recently, by laying the line between Hingoli and Khandwa, the metre gauge was connected from north to south and a link between north and south established. But there is yet a break of metre gauge in the south. That line has to be laid. Long ago, this line was recommended by both the Mysore and the Madras Governments. But it was not taken into consideration and so that matter was lying idle. For various reasons, this line is important, and so, both the Governments recommended that this line should be taken up. Yet. nothing was done, though the Railway Minister promised that a west coast railway line would be soon laid. This break is between Chamarajanagar in Mysore State and Coimbatore in Madras State. It is a distance of about 80 miles. If this line is laid, I think a direct railway line could be obtained from Trivandrum in the south to Punjab in the north, through a metre gauge along the west coast.

It was mentioned that roads run parallel to railways in Madras State. It is not a special feature of Madras

State. Roads run parallel to railway lines in other States also. For instance, there is a road from Delhi to Agra and it also runs parallel to the railway line, and the railways also are putting up a number of overbridges so that the traffic on the roads may not be unnecessarily hindered. In fact, the railway lines were laid parallel to the roads everywhere. So, to say that roads are parallel to railway lines . only in certain of the country is not parts Such a feature does not correct. hinder the railways in anyway from carrying goods. That was admitted by the Railway Minister himself in his reply to the debate on the railway budget. There will be no competition between the railways and the roads.

Again, mention was made about the losses in the Southern Railway. That is not a special feature of the Southern Railway only. After all, the route mileage covered by the Southern Railway in the Madras State is only one-sixth of its total route mileage under its jurisdiction.

The next point that I would like to mention is about the third class travel. The Railway Minister announced in this House as well as in the other House that there would be no relief from overcrowding in third class coaches. That may be so, but by saying so, he also means that he is not in a position to ask the railways to carry all the passengers who want to travel third class. That is not my point. My specific point is about the real overcrowding in a third class coach. What do the railways do to prevent this overcrowding? How does this overcrowding come about? They issue more tickets than the accommodation warrants. They put up in bold letters, "To seat 45" or whatever be the number. But they issue as many tickets as are demanded and so the overcrowding is there. The railways complain about ticketless travel, but by issuing more tickets than the seats warrant, they voluntarily encourage the ticketless travel. So, by limiting the num-

for Grants 4234 (Railways)

ber of tickets to be issued, as they do in the case of upper classes, they could prevent overcrowding in third class coaches, and thus avoid the present inhuman conditions of travel in third class compartments especially in the case of passengers travelling long distances.

There is also a question of principle or legality in regard to this matter. That is, a bus cannot take more than the prescribed number of passengers. The driver cannot take even one passenger extra, whereas the railways allow as many passengers as are offering themselves for travel, even though the railways have mentioned that there is accommodation for such and such number of passengers only. They must give consideration to this aspect and see that only the prescribed number of passengers, especially in the case of distance passengers, should long travel, and not more.

The next point I would like to mention is about the seat. While the Railway Minister was pleased to take Her Majesty the Queen to the Integral Coach Factory at Madras, the Queen remarked that the third class seats would be very hard for the passengers to sit. We can imagine the people travelling hundreds of miles in these coaches, sitting on such hard seats. The railways have provided many amenities to third class passengers, and so why not they provide softer seats in third class coaches? Even if such an amenity costs a little more, I think the fare can be increased, and the long distance traveller will be quite willing to pay more.

The Railway Minister was saying that he would be abolishing the second class. I mention this, because by abolishing the second class, more accommodation will be available to the third class passengers even without soft seats.

[SHRI JAGANATHA RAO in the Chair]

Apart from that, if a softer seat is provided and if a limited number of

[Shri Nanjappan]

people alone are allowed in the third class, the second class can be totally aboished in the interests of third class passengers.

One more point which I would like to make is regarding the air-conditioned coaches. Air-conditioned coaches are attached even to the trains which run only short distances. For instance, to trains running from Bangalore to Madras or from Madras to Coimbatore air-conditioned coaches are attached. After all the distance is very short and the nights on these routes are fairly cool, and there is no coaches in need for air-conditioned these trains. Why I am mentioning this is because I am told that these air-conditioned coaches are so heavy that in their place two third class coaches can be added. If that is so, why should there be these air-conditioned coaches in short distance trains? By attaching air-conditioned coaches to these trains, not only is the third class traveller affected but even the first class traveller is affected on those days when the air-conditioned coaches are put in. The number of seats are less in these coaches and the passenger suffers. Not only that: reservation at intermediate stations is also not permissible, and to that extent also, the passenger suffers.

The next point I would touch upon is catering. Here again, the Railway Minister was very much pleased to say that the food supplied by the railway department is very good and that departmental catering is going to be resorted to more and more. I am glad about it. But the quality of food, especially the South Indian vegetarian food, is very poor. The rice water is thrown out; so also, the water in which the vegetables are boiled is also thrown out. So, the nutrition is lost. Mere plantain curry or some cheap tubers are supplied. Formerly they used to give dal separately, but that is not to be seen nowadays. What we get to gulp some rice with is some tamarind solution called sambar or rasam. Ghee is very little and the butter milk or curd is not good. So, my submission is that the South Indian vergetarian food that is supplied should have some calorie value and it should be a balanced diet. The railways should see that they supply a balanced diet which has some calorie in it and also some nutrition.

14 hrs.

Regarding the sanitation asthe way in which pect of the food is supplied, it is not done in a sanitary way at all. There must be some principle in doing these things. As a traveller, I can say that the plates are being carried by one man. Formerly there used to be two plates, but now all the plates are heaped up one above the other without any covering. What actually happens is the bottom of the upper plate touches the food in the plate below and it is all exposed. They bring it in that way. This sort of catering is not at all good and it cannot be said to be sanitary. So many times one can find foreign matters also in the food.

My suggestion is, just as they have trained men for so many purposes, for catering and cooking also, people should be taken and given training. If that is done, better food can be supplied and better sanitation can be maintained. Not only the food supplied is not in a sanitary condition, but the station yards also are in a bad condition. If you see Howrah station, for example, it is in such an unsanitary condition. Sanitation must be improved and I hope the railway authorities will apply their mind to it.

भी मासर (रत्नागिरि) : सभापति महोदय, रेलवे की की डिमाण्ड्स पर जो बहस हो रही है, उनमें बोलने का जो मापने मुझे मबसर प्रदान किया है, उसके लिए में मापको भन्यवाद देना हूं। मैंने इन डिमाण्ड्स पर कुछ कटोती प्रस्ताब पेश किये हैं मौर उनमे से कुछ पर में बोलना चाहता है। सबसे पहले मुझे बम्बई की सुवर्वन लोकल रेलवे के बारे में कहना है। बम्बई की झाबादी दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। हाल ही में जो सेंसस दुझ। उसके फलस्वरूप झापको पता चल जाएगा कि वहां की झाबादी ४४ लाख तक जा पहुंची है झौर जो रेल व्यवस्था है, वह इन सभी लोगो की जरूरतों को पूरा करने में सर्वथा ग्रसमर्थ सिद्ध हो रही है। इसका परि-णाम यह होता है कि जो लोकल ट्रेंस हैं, वे हमेशा ही लेट हो जाया करती हैं.....

रेलवे उपमंत्री (भी शाहनेवाल जा) : आबादी को रोकना चाहिये।

भी द्यासर : ग्राबादी जव रुकेगी तव रुकेगी लेकिन जो बढ़ चुकी है उसके लिए तो ग्रापको कुछ न कुछ प्रबन्ध करना ही होगा ।

मैं कह रहा था कि लोकल ट्रेन्स जो हैं वे हमेशा ही लेट हो जाती हैं मौर दो दो या चार चार मिनट नहीं झाथ झाथ घंटे लेट पहुंचती हैं। इस का परिणाम यह होता है कि जो कर्मचारी हैं वे झाफिस लेट पहुंचते हैं भौर उन को मनिष्छापूर्वक माधे दिन की खुट्टी लेनी पड़ जाती है। इस बढ़ती हुई झाबादी को देखते हुए झौर साथ ही साथ जो इंडस्ट्री वहां बढ़ रही है उस को देसते हुए वहां की रेल-व्यवस्था में कुछ सुधार करना झावध्यक हो गया है। इस के लिये कुछ विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि स्थिति में सुधार हो । मैं झाप को झपने भनुभव से बतलाता हूं कि १ मार्च को मैं पूना जा रहा या भौर बम्बई से जो डेक्कन एक्सप्रेस खूटती है उस में मैं बैठा हुमा था। बह गाड़ी मस्जिदबंदर था कर एक घंटा तक दफी रही। जब हम ने पूछा कि गाड़ी क्यों इक गई है तो हमें जवाब दिया गया कि सिगनल नहीं हुआ है। जब हम ने पूछा कि सिगनस क्यों नहीं हुआ है तो जवाब मिला कि ट्रफिक बहुत बढ़ गया है इस बास्ते भकसर गाड़ियां भेट हो जानी है।

हर दूसरे तीसरे दिन यह चीज होती **रहती है।** वहां पर ट्रेंस को भाष घंटा, घंटा स्कना पड़ता है। इस के बारे में माप को मावश्यक उपाय करने होंगे । वहां के यात्रियों को मावश्यक सुविधायें झाप को पहुंचानी होंगी । चूंकि माबादी बढ़ रही है मौर साथ ही साथ इंडस्ट्रीज भी वहां नई नई चालू हो रही हैं, उन की मावक्यकलामों की पूर्ति करना माप का कर्त्तक्य है। वहां जो स्टेशन हैं वे भी पुराने हो गये हैं भौर वे मुसाफिरों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं । जब भाप स्टेशनों में सुघार कर रहे हैं तो माप का उघर भी घ्यान जाना चाहिये । वहां पर जो खोटे छोटे स्टेशन हैं वे वैसे के वैसे ही हैं। उन को बदलना मावश्यक है मौर जहां पर इस समय स्टेशन नहीं है भौर वहां पर स्टेशन की भावश्यकता है, वहां भाप को नया स्टेशन बनाना होगा ।

मब मैं मोवर-बिजिज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पारले, मंथेरी मौर मालाड स्टेशनों पर मोवर-ब्रिजिज का होना बहुत भावश्यक है। इन की व्यवस्था न होने के कारण ट्रेफिक माथ माथ मौर पौन पौन बंटे तक रुका रहता है। मैं माशा करता हूं कि इस भोर माप ध्यान देंगे मौर वहां पर मोवर ब्रिजिब की व्यवस्था कर देंगे। बम्बई के जो सुबबंन एरियाज हैं, वहां पर जहां जहां मी मोवर ब्रिजिज की मावश्यकता हो, य बनाय जाने चाहियें ताकि ट्रफिक न इकने पाय।

पूना धौर लोनावला के सोगों की एक मांग है जिस की तरफ मैं घाप का ध्यान दिशाना चाहता हूं । पूना एक बहुन बड़ा इंडस्ड्रियल टाउन है धौर लोनावला तक बड़ी बड़ी ईंडस्ट्रीच खड़ी हो रही हैं । वहां पर धार्डिनेंस फैक्ट्री धौर मिलिट्री हिंगे है । बहां की चनता की मांग है कि लोनावला पूना सैक्झन को भी बम्बई मुबर्बन सक्झन के समान ही मुबर्बन सैक्झन माना जाय । इस का घर्ष यह होगा कि जो किराया बम्बई

[श्री मासर]

सुंबर्बन एरियांज में लिये जाते हैं, वही किराबे पूना से लोनावला तक लिये जायें । यहां भी यह लोकल ट्रेन है । जिस सरह से यहां की भाबादी बढ़ रही है, उस को दे खते हुए उन की इस मांग को स्वीकार करना ग्राप के लिये मुश्किल नहीं होना चाहिये । मैं चाहता हूं कि इस मोर विशेष रूप से घ्यान दिया जाय जब ग्राप बम्बई में कम किराया लेते हैं भौर वहां के लोगों को विशेष सहूलियतें देते हैं, तो कोई यजह नहीं है कि वही सहूलियतें देते हैं, तो कोई यजह नहीं है कि वही सहूलियतें ग्राप पूना वालों को न दें। वहां पर नई नई इंडस्ट्रीज शुरू हो रही हैं भौर भाबादी भी बढ़ती जा रही है, इस दृष्टि से उन की इस मांग पर सहानुभूति से विचार करना ग्रावश्यक है ।

मब मुझे पूना-मिराज-कोलहापुर लाइन के बारे में कुछ कहना है । वहां की मीटर गेज लाइन को बदलाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन भभी तक कुछ नहीं किया गया है । मंत्री महोदय भी हर साल जब बजट ग्राता 🖁 तो इस को बाड गेज में बदलने का संकेत करते हैं । तीन चार वर्ष से एसा ही होता ग्रा रहा है। लेकिन भभी तक कुछ नहीं किया गया है । प्रथम योजना समाप्त हो गई, द्वितीय समाप्त हो गई है, लेकिन इस बारे में कोई ठोस कदम नही उठाया गया है। भाज भी हम **देखते हैं कि सबँ के लिये कुछ रकम रखी** गई है लेकिन उससे सन्तोष होने वाला नहीं है। हर साल यह चीज माती है लेकिन क्रुम प्रगति होती हो, एसा दिखाई नही देता है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस के बारे में कुछ ठोस कदम उठाय ताकि लोगों को सन्तोष हो सके । कोलहापुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, शुगर फैक्ट्रीज है, सूती कपड़े की मिलें हैं । सांगली, माधवनगर, कराड, नीरा, सतारा ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं जोकि तिजारत के सैंटर है, इंडस्ट्रियस एरियाज हैं, भीर यहां से माल परिवहन की उचित व्यवस्था न होने के कारण बहुत असुविधा होती है । यात्रियों

को लाने से जाने की मच्छी व्यवस्था न होने कें कारण भी काफी असन्तोष वहां पाया जाता है। इन दोनों दृष्टियों से यह मावश्यक है कि इस मीटर गेज को बाड-गेज में बदस दिया जाय। मैं माशा करता हूं कि शीघ्र ही इस मोर घ्यान दिया जायगा।

ग्रब मैं नई लाइनों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इस के मामले में महाराष्ट्र के साथ बड़ा अन्याय किया गया है, एसा मैं मानता हुं। महाराष्ट्र सरकार ने नई लाइनों के बारे में जो सूची रेलवे मंत्रालय को भेजी है, उस में से केवल एक रेलवे लाइन की स्वीकृति हमारी सरकार ने दी है। बजट स्पीच में माननीय मंत्री जी ने दीवा-पानवेल का ही जिक किया है ग्रीर वहां ही एक नई लाइन की बात कही है। चूंकि महाराष्ट्र की आबादी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और वहां पर इंडस्ट्रीज भी बढ़ती जा रही हैं, इस वास्ते जो भी सूची महाराष्ट्र सरकार ने माप के पास भेजी है, उस की मोर ध्यान दिया जाना बहुत भावश्यक है। भभी तक ऐसा नहीं किया गया है। हमारे मंत्री जी ने कहा है कि पिछड़े हुए इलाकों को भागे बढ़ाया जाना चाहिये । माननीय मंत्री जी समझते हैं कि इस दीवा-पनवेल लाइन से कोंकन का विकास हो सकेगा । लेकिन माननीय मंत्री जीको पतानहीं है कि पनवेानको में कहां है। पनवेल बम्बई का एक सूबर्बन एरिया माना जाता है। पनवेल में रेल होने से कोंकन का विकास नहीं होगा। कॉकन का विकास होना भावश्यक है भौर इस इच्टि से पनवेल से रेस को चिपलून तक बढाना झावध्यक है। यह केवल ६०-७० मील का एक टकडा है। यहां पर रेल का होना अत्यश्विक झावश्यक है। जब माप ने पनबेल से लाइन बिखाने का निर्णय किया है तो माप उस से माबे बढ़िये और इस को चिपलून तक बढ़ाइये। चिपसून के पास ही कोयना प्रोजेक्ट है बडा से विजली मिलने बाली है, वहां एक बाद

का कारखाना खुलने वाला है, पेपर फैक्ट्री हीने वाली है, झौर छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होने वाली हैं, इस दृष्टि से वहां पर रेलवे का जाना झावक्यक है। मैं चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से पनवेलचिपलून लाइन के लिये झावकावासन दिया जाय।

दसरी बात में रिटायर्ड रेलवे कमचारियों के बारे में कहना चाहता हं। उन्होंने रेलवे मंत्रालय को भ्रपना रिप्रेजेन्टेशन दिया था। लेकिन उन की बात नहीं सुनी गई । मझको ऐसा लगता है कि उन की बात पर सहान-भति से विचार किया जाना चाहिये क्योंकि माज रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों की हालत बहत खराब है। सन १९४७ की जो पहली पे कमिशन की रिपोर्ट थी उस में उन की पेंशन के बारे में जो कुछ दिया गया था उस पर विचार नहीं किया गया । सन १६४७ के बाद पेंशन देने पर विचार किया गया, लेकिन उन को पतानहीं था। जब सन् १६४७ में पे कमिशन ने इस बारे में सिफारिश की तो सन १९४७ से पेंशन की यह योजना क्यों नहीं चालू की गई । चुकि बाद में की गई इसलिये यह प्रयत्न किया जाना चाहिये कि रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों को भी उस का मनाफा मिले ।

स्पीड के बारे में एक या दो बातें बतलानी मावश्यक हैं। यहां पर प्रक्सर स्पीड की चर्चा होती है। हमारे यहां डेक्कन क्वीन है यह पहले पूना से बम्बई ढाई घटों में जाया करती थी लेकिन मब उस को साढ़े तीन या पौने चार घटे लग जाते हैं। फेंटियर मेल को जो पहले साढ़े २२ घटे लगा करते बे मब उस में २४ घटे लगते हैं। फेंटियर मेल को जो पहले साढ़े २२ घटे लगा करते बे मब उस में २४ घटे लगते हैं। मलिर, हम पीछे की मोर क्यों जा रहे हैं? जबकि नया जमाना मा रहा है तो हमारी रेनों की जो स्पीड पहले थी उस में मौर कमी हो रही है, यह ठीक नहीं है। इसमिये जो हमारी मेल ट्रेनें या एक्स्प्रेस ट्रेने हैं उन की स्पीड को बडाने का प्रयत्न किया जाय।

ऐक्सिडेंटस के बारे में भी मैं कहना भाहता ह । विशेषकर जो ऐक्सीडेंट पिछले भार छः दिन में हमा उस की भर्मा मैं करना भाहता ह । उस के पहले जो ऐक्सिडेंट हुमा बह तो चलती गाड़ी में हमा था, उस की बात तो छोड़िये, बम्बई हावडा एक्स्प्रेस सडी थी, नागपुर स्टेशन पर उस पर दूसरी ट्रेन ग्रा कर टकरा गई। उस में ६३ पैसेन्जर घायल हए । वैसे ही स्थिति जो एक्सिडेंट परसों हम्रा उस में हई। रेलवे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी थी, दूसरी गाडी ने आ कर उस में टक्कर दी। उस में १२ मादमी मर गये झौर कुछ घायल हो गये। झाखिर इस सरह के ऐक्सिडेंटस की क्या वजह है ? क्या वहां पर कोई पोटर नहीं होना जोकि गाड़ी के खडे होने का साइन बतला सके ? खड़ी गाडियों के साथ एक्सिडेंट्स होना बड़ी खतरनाक बात है, इसलिये इस तरफ ध्यान दिया जाय ।

यहां पर रेलवे केटरिंग के बारे में कूस कहा गया । हमारे एक भाई ने कहा कि फड बहुत खराब मिलता है, फिर भी रेलबे केटरिंग सब जगह चलाई जाय । जो लोग कुछ मुखी हैं उन को भी दुखी करना चाहते हैं। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि जब प्राइवेट केटरिंग चलती थी तो लोगों को मच्छी तरह से खाना मिलता था भीर सब कुछ ठीक था। प्रव हम ने कुछ जगहों पर रेलवे के हाथों में उमे दे दिया है। डिपार्टमेंटल कैटरिंग होने के बाद घनाज जो मिलना है वह बहत खराव मिलता है भौर दाम ज्यादा देना पहता है । इस स्थिति को देखते हुए हमारा केटरिंग डिपार्टमेंट जो बैठा हमा है उस सिस्टम को बदलना बाहिये। उस में करप्शन बहत है, बिना करप्शन के इस तरह की बातें महीं हो सकती हैं। पहने प्राईवेट को उस से मनाफा मिलना या भौर मण्छा भनाज मी सोगों को मिलता था। लेकिन साज इस में बाटा हो रहा है । मै रेलवे मंत्रालय से प्रार्थना कर्बना कि इस के बारे में पूरी बोज बीन

[श्री मासर]

की जाय भौर ग्रगर हम इस काम को टीक से नहीं कर सकते तो इस को छोड़ दिया जाय भौर जो प्राइवेट केटरिंग करने वाले है उन के हाथ में इसे दे दिया जाय ।

माखिर में मैं रेलवे डिपार्टमेंट की चोरियों के बारे में कहना चाहता हूं । इन चोरियों में कोई कमी नहीं हई है। हम ने स्पेशल रेलवे रिजवं पुलिस रख दिया, भौर इस के पर चलचं भी किया, लेकिन ग्राज तक इस के बारे में कोई कमी नहीं हई । में ने पिछले साल प्रइन पूछे थे। दीवा एक स्टेशन है जोकि चोरियों का मड्डा है । वहां रात भौर दिन का कोई सवाल नहीं है, बराबर रात दिन रेलवे का माल चोरी जाता है। पता नहीं लगता कि रेलवे डिपार्टमेंट ग्रौर रिजर्व पुलिस सो गया है या क्या हम्रा है। सेकिन यह जरूर है कि इस को कोई रोक नहीं सका है। मैं तो समझता हं कि इस में हमारे अफसर शामिल हैं, भौर यही कारण है कि पूना ग्रौर कल्याण स्टेशन याडं चोरियों के झड्डे बन गये हैं। इस चीज को रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

भी रा० स० तिवारी (खजुराहो) : सभापति महोदय, ग्रभी दो तीन दिन से रेलवे की बहस चल रही है। इस में भाधिकतर यह कहा गया है कि रेलवे के काम में बड़ी शिथिलता है। इस के बारे में मैं यह बतला **देना** चाहता हं कि रेलवे ने दूसरी योजना में जिस तरह से काम किया है वह सराहनीय है। इस योजना में रेलवे ने सब से बडा काम यह किया है कि जो भीड़ भाड़ चलती थी उस को कंट्रोल करने के लिये २३ परसेन्ट गाडियां भौर चलाई । इसलिये झाज भी भीड़ तो होती है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी पहले होती थी। दूसरा काम जो रेलवे ने किया है वह यह है कि पहले क्लास, दूसरे क्लास ग्रीांर तीसरे क्लास के कर्मचारियों के ग्राजित ग्रवकाश के समय को, १ ग्रत्रैल,

सन् १९४७ को जो आर्डर जारी हुन्रा था उस के अनुसार एक लेवेल पर ला दिया है। दोनों ही के लिये ग्रब एक सा समय कर दिया गया है। तीसरी बात जो रेलवे विभाग ने किया है वह यह है कि १६ नवम्बर, १९४७ को यह तय किया कि रेलवे के सभी कर्म-चारियों को ग्रब पेंशन मिला करेगी । यह एक बहुत बड़ा काम किया गया है । चौथा सब से बड़ा काम उन का यह है कि भ्रगस्त, १९४९ में वेतन कमिशन ने जो रिपोर्ट दी थी उस में जो कुछ कहा गया था उस को करीब करीब रेलवे विभाग ने मान लिया है, जिस में १३ करोड रु० सालाना से ज्यादा का खर्च भ्रायेगा । यह काम थोडे नहीं हैं । क्रिटि-सिज्म करना ग्रासान है परन्तू वास्तविकता को देखना चाहिये । हां यह जरूर है कि जितना काम होना चाहिये था उतना नहीं हो सका है हालांकि वह काम होना भावश्यक था।

सब से पहली बात तो यह मैं निवेदन करूंगा कि म्राज जो हमारी रेलवे में मामदनी बढती नहीं दिखाई देती । उस का एक कारण यह है कि म्राजाद हिन्दुस्तान घीरे घीरे उठ रहा है जिस की वजह से सेवायें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उस बढ़े हुए खर्च का मुकाबला करने के लिये रेलवे की भ्रामदनी बढ़ाई जानी चाहिये जोकि नहीं बढ़ रही है । हमारी बसेज का जो काम चल रहा है यह भविष्य में रेलवे के लिये एक खतरा साबित होगा । इसलिये उस की सीमा नियत की जानी चाहिये। सब से बड़ी जो शिकायत हम को भाप से है वह यह कि बहुत सी रियासतों को मिला कर माप ने बड़े बड़े प्रदेश बनाये हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश है। एक मध्य प्रदेश में ही ४०, ४० या ६० रियासतें मिलाई गई हैं, जोकि छोटी छोटी रियासतें बीं । उन रियासतों में रेल तब भी नहीं थी भौर भव भी जब हमारे मंत्री महोदय रेलों की प्लैनिंग करते हैं तो उन का ध्यान इस की तरफ नहीं जाता कि पिछड़े हुए इसाके हैं, जैसेकि

ब्देलखंड, उन को लिया जाय । म्राप ब्देलखंड में कहीं पर रेल नहीं पायेंगे ६०, ७० मील इघर उघर। छब से बड़ी बात जो मैं झाप के सामने रखना चाहता हूं वह है यह कि सीधी जिला में सिगरौली एक तहसील है, जहां पर ٤०० वर्ग मील में कोयले के लिये सर्वेक्षण किया गया । वहां पर बहुत ज्यादा कोयला है, लेकिन रेलों का कोई प्रबन्ध नहीं है, जबकि गुजरात के बारे में यह खबर है कि वहां कल कारखाने बन्द होने वाले हैं क्योंकि कोयला नहीं पहुंचता है । इस लिये मेरा निवेदन है कि सिंगरौली से रीवां तक सीधी रेल लाइन बनाई जाय जोकि रीवां, सतना, पन्ना, छतर-पूर, टीकमगढ़, ललितपुर होती हुई सीधे गुजरात तक पहुंच सकती है। इस से माप को कोई ३०० मील लम्बी रेल लाइन निकालनी पड़ेगी जबकि माज 200 भीतो चल किर गुजरात में पहुंचना पड़ता है । इस तरह से बीना **भौर** गुना को भी ए**क** रेल लाइन मिल जायेगी । इसलिये मैं चाहता हूं कि यह रेल लाइन बनाई जाय क्योंकि इस से बुदेलखंड की शिकायत भी दूर हो जाती है भौर सिंगरौली से एक सीधी लाइन भी मिल जायेगी जहां पर इतना कोयला है कि झगर झाप १४ या २० साल भी लें तो भी सतम नहीं होगी ।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि बहुत से जिले रेलवे से कनेक्टेड नहीं हैं। उन के बारे में मेरा निवेदन है कि वहां पर कम से कम माउट एजेंसी ही बना दी जाय जिस से कि माल के माने जाने में सहलियत हो जाय ।

बहुत से माल पर रेलवे को नुकसान पूरा करना पड़ता है। लेकिन जो नुकसान करने के लिये जिम्मेवार होता है उस को नहीं पकड़ा जाता। भगर ऐसा किया जाय तो मैं। समझता हूं कि नुकसान बहुत कम होने लगे सेकिन ऐसा नहीं होता।

() जहां तक माल की ढुलाई का संम्वन्ध है बहुत सी चीजें तो सीघी ट्रकों से चली जाती है, घाप के लिये बचता ही क्या है, रेसवे से सड़ने गलने वाली चीजें, जैसे फल, साग भाजी और तम्बाकू मादि भेजी जाती हैं जिन का किराया कम है और जो जगह ज्यादा लेती हैं। यही चीजें माप को मिलती हैं। उस में भी दिल्ली के फल वालों को शिकायत है कि नागपुर से जो संतरे माते हैं उन को माने में सात दिन लग जाते हैं। यह सड़ने वाली चीज है भौर इतने समय में खराब हो जाती है। इस के लिये मधिक सुविधा मिलनी चाहिये।

मेरे यहां हिदूस्यान में पान सबसे ज्यादा होता है । हरपालपुर भौर महोवा से पान लदता है, लेकिन जिस दिन वह भाता है उस दिन नहीं लादा जाता, दूसरे दिन लादा जाता है । कभी कभी तो वह दोपहर में भूप में पड़ा रहता है । भौर यहां भाने पर सड़ जाता है भौर फेकना पड़ता है । लोगों ने भव रेलव के बजाय सीघे ट्रक से पान लाना शुझ् कर दिया है भौर वह उसी दिन यहां पहुंच जाता है । यदि इन खोटी छोटी चीजों की भोर घ्यान न दिया गया तो रेलवं का माल का ट्रेफिक सदम हो जायगा ।

माप ने जो केटरिंग में भोजन की व्यवस्था की है वह संतोषजनक नहीं है । मेरे साथी मभी उस की शिकायत कर रहे चे कि वह सन्तोषजनक नहीं भौर उस को प्राइवेट कर दिया जाय । जब यह व्यवस्था प्राइवेट कर दिया जाय । जब यह व्यवस्था प्राइवेट हायों में थी तो शिकायत की जाती ची मौर कहा जाता था कि सरकार इस को म्रपन हाथ में ले ले । लेकिन इनना तो जरूरी है कि कुछ तौल निध्चिन कर दी जाये । मभी जो चार चपा तियां देते हैं व तोल में एक खटांक भी नहीं होती हैं । तो कुछ तोल रखें पाव भर में या माधा पाव में चार चापा-तियां बनावी जाय । कुछ लिमिट रखनी चाहिये ।

भी झाहनवाम जा : लिमिट है।

भी राश्तेत्र ।तवारी : लेकिन उस पर भ्रमम नहीं होता । इस पर भी भ्यान [श्री रा० स० तिवारी] देना चाहिये । मैं चाहता हूं कि मेम्बर पार्लीयामट भी इस चीज को देखे मौर इस की शिकायत मंत्री महोदय से करें ।

झांसी से मानकपुर जो लाइन जाती है उस में कोई तेज चलने वाली गाड़ी नहीं है। सब घीमी चलन वाली गाड़ियां हैं। भौर फिर उन में लदान भी होता है। इस के हर स्टेशन पर ब लेट हो जाती हैं। एक बार में न प्रायंना की थी श्रौर झार्डर हुआ था कि इस लाइन पर एक एक्सप्रेस गाड़ी चलायी जायगी, लेकिन फिर कहा गया कि उस लाइन के पुल कमजोर हैं, इसलिय भारी इंजन उन पर नहीं चल सकते है मेरा निवेदन है कि धगर पुल कमजोर हैं तो उन को जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाय ताकि यहां यातायात की सुविधा हो सके।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। जो पिखड़े हुए प्रदेश हैं भौर जो रियासतों से बनाये गये हैं उन के लिये घाप कम से कम यह करें कि जो पुरानी पटरी है उस को डार्ले भौर जो पुराने डिब्बे भौर इंजन हैं उन को जोड़ कर एक रेल बना दे ताकि कुछ कमी पूरी हो। हम लोग घभी उसी में संतोष कर सैंगें। घाप को सिर्फ ट्रेंक बनाने का खर्च करना पड़ेगा, बाकी तो वही सामान होगा जो कि घाप रही में नीलाम कर देते हैं।

एक माननीय सबस्यः एक्सीडेंट के सिये जिम्मेदार कौन होगाः ।

बी रा॰ स॰ तिवारी : पहले तो माल डोया जायेगा, फिर जब पैसेंजर चले तो एक्सीडेंट का सवाल पैदा होगा ।

मेरा निवेदन है कि उन स्थानों पर सास भ्यान दिया जाय जहां कि झभी रेल नहीं है। वहां झगर रेले बनायी जाय तो झच्छा होगा ।

Shri Kodiyan (Quilon-Reserved-Sch. Castes): Mr. Chairman, Sir, though I have moved a number of cut motions on various subjects, I wish to confine myself to the demands of the people of Kerala with regard to rail travel.

Mr. Chairman: Only ten minutes are allowed.

Shri Kodiyan: Only ten minutes?

First of all I shall refer to the need for opening some new lines in Kerala. I do agree with and support the view taken by the Railway Ministry that in opening new lines preference should be given to those lines which will serve the industrial centres and mining areas. But importance should also be given to areas which are economically and industrially backward because opening of new lines there will, to a very large extent, facilitate the growth of new industries, trade and commerce in these areas. Viewed in this background Kerala needs special consideration.

I find that a sum of Rs. 120 crores have been provided for opening new lines during the Third Five-Year Plan period, but not a single pie has been allotted for opening of new lines in the south. Several hon. Members from the south, who have spoken, have already referred to this aspect.

Coming to Kerala, the Kerala Government have suggested some seven or eight new lines to be taken up in Kerala. We have demanded these lines not merely for the convenience of passengers but also for the reason that for the movement of goods also these new lines should be undertaken in Kerala. I do not want to mention all the lines proposed by the Kerala Government, but I should mention a lines. The Tellicherry-Coorgfew Mysore railway line was approved by the Ministry. This line was even surveyed in 1955. But so far no action has been taken. I do not know why no action has been taken and whether this has been dropped. I want an explanation about that from the hon. Minister.

Then there is another line which was surveyed even before the Tellicherry-Coorg-Mysore line was surveyed, that is, the Trichur-Kollengode line. That also seems to have been abandened now. The Tellicherry-Coorg-Mysore line, if constructed, will be the only line that will connect Kerala with Mysore.

Then there is another line proposed by the Kerala Government, namely, the Kayamkulam-Ernakulam line via Alleppy. Alleppy is an important industrial centre on the west coast and goods from the Alleppy area will have to be moved by country boats. It will take much time and it is too expensive also. If a line is constructed via Alleppy connecting Kayamkulam with Ernakulam, it will facilitate the development of this coastal area.

Then the Trivandrum-Cape Comorin line is a very important line. The hon. Deputy Minister, Shri Ramaswamy, also, I think, has once expressed himself in favour of opening that line. But nothing has been done so far

There is a proposal to have a chord line in my constituency connecting Punalur on the Quilon-Shencotta line with either Mavelikkara or Chenganoor or Thiruvalla. This will also help the hill produce to be brought to Cochin Harbour.

Then I come to another point, namely, that of the capacity of the existing The line lines. connecting Cochin Harbour with Shoranur was constructed many years ago. Since then, Cochin Harbour has developed and traffic has also increased considerably. Due to the limited capacity of this line there is a lot of trouble in Cochin Harbour. The main reasons for demurrage on goods in Cochin Harbour is this limited capacity of this line. Goods are being held up there because they cannot be cleared due to the insufficient capacity of this line. As far back as 1952 the Cochin Port authorities had requested the Railway Board to double this track between Cochin Harbour and Shoranur but nothing has been done so far. I do

not know whether there is any proposal for doubling this track during the Third Five-Year Plan period.

So many hon. Members have referred to the problem of overcrowding. specially in the third-class coaches. this The hon. Railway Minister has time also, as in previous years, stated that the problem of overcrowding will remain there for the next few years also. I do agree that with the limited number of coaches and rolling stock it may not be possible to eliminate overcrowding completely in the near future. But something has to be done where overcrowding has become the greatest problem. For instance, with regard to the main trains that מנוד between Kerala and Madras, whether it be the Mangalore Mail or the Cochin Express or the Trivandrum Express, the problem of overcrowding is very acute. It will be very difficult to get accommodation from Madras in these trains to Kerala. Last year I had the experience of travelling in a third class compartment of the Cochin Express-I did not get accommodation either in first or second class. In that compartment I could sit up to Coimbatore, but from Coimbatore onwards I could not even sit, because from all the important stations from Coimbatore onwards poeple began to come and crowd the compartment. So it was difficult even to sit. This was my own personal experience.

Then, the train that runs between Mangalore and Cochin Harbour is always crowded, whether it is coming from Cochin Harbour or going to Cochin Harbour. Recently I read in a local newspaper a statement by an ex-Minister who had occasion to pull the alarm chain to stop this train. In order to get a seat he had entrained from Cochin Harbour. Af er four or five stations the compartment got so by people from overcrowded the wayside stations that he felt-he says in his statement-that the passengers inside the compartment would be suffocated to death, and so he had to pull the alarm chain. The guard came and told him that he was helpless,

[Shri Kodiyan]

because from every station—as Shri Nanjappan informed the House just now—tickets were issued indiscriminately to all the passengers who came for tickets. Such is the state of affairs there. I would, therefore, request the hon. Minister to run an additional train between Mangalore and Cochin.

Then, Sir, I am glad to find that the hon. the Railway Minister is paying more attention to the third-class passengers, and sleeping coaches have recently been introduced on various routes. Sleeping accommodation has been provided in one train in Kerala also, that is in the Mangalore Mail. But practically this is of no 1186. because this accommodation is provided only for passengers travelling over 700 kilometres. That means only those passengers who would travel to the farthest end of that route from Madras to Mangalore, will get this accommodation.

Shri Shahnawax Khan: It is available for everybody.

Shri Kodiyan: No, it is not available.

Shri Shahnawas Khan: It is available if you pay for it.

Shri Kodiyan: That is true. Every passenger to Kerala, whatever be his destination, has to spend a night in the train before the train reaches the borders of Kerala. I would, therefore, requst the hon. Minister to introduce these sleeping coaches in other trains also, that is in the Cochin Express and Trivandrum Express. All the passengers who travel more than 500 kilometres should be given this sleeping accommodation without any additional payment.

You will be surprised to find that most of the main railway stations in Kerala have no retiring mooms. And you will be further surprised to find that even at the railway station at a divisional headquarters, like Olavakkot, there is no retiring room facility. Cannanore, Ernakulam, Quilon, Calicut, all these are very important stations; they are always crowded and there is heavy traffic, but there are no retiring rooms at these places.

Then there is the question of overbridges. We have put in this very House several questions about these overbridges. But I find that in a place like Shoranur, where a lot of shunting is also being done, there is no overbridge. Normally, if a train is coming, one will have to wait for half an hour where there is no overbridge. But at Shoranur you will have to wait for more than one hour if there is shunting also. That is the state there. Similarly, there are some other places also where overbridges have to be constructed. These things require the attention of the Railway Ministry. I request the hon. Minister to look into these grievances and take necessary action.

पंडित द्वा० ना० तिचारी (केसरिया) : सभापति महोदय, मुझे रेलवेज की डिमांड्स पर कई बातें निवेदन करनी हैं लेकिन मैं चूंकि भापकी घंटी से डरता हूं इसलिये कम ही बात करूंगा । इसलिये कृपया घंटी जरा देर से बजाइयेगा क्योंकि मैं तो उसको पूरी तौर से मानने वाला हं

सभापति महोवयः दस मिनट का समय है।

पंडिल द्वा० ना० तिवारी : ठीक है जैसी म्रापकी माज्ञा।

इस रेलवे बजट को देखने से पता चलता है कि रेलवेज की चारों मोर प्रगति हुई है। सब मोर कुछ न कुछ प्रगति हुई दृष्टिगोचर होती है इसलिये रेलवे मंत्री महादय को बहुत बधाइयां भी मिली हैं।

मैं शुरू में रेलवे मिनिस्टर साहब को कह देना चाहता हूं कि उनको यह माध्वासन देना चाहता हूं कि मैं किसी चीज की मांग करने के लिये खड़ा नहीं हुमा हूं क्योंकि मैं

पुर भौर पटना दौड़ते फिरते हैं । भगर मंत्री महोदय इसके लिए उदाहरण चाहें तो मैं उनके सामन कई उदाहरण रख सकता हूं ।

भव यह जो हड़ताल हुई थी वह केवल महीना बढ़ाने के कारण ही नहीं हुई थी बस्कि उसमें भौर भी बहुत से छोटे-छोटे ग्री वियन्सेज भी शामिल थे। जिनसे कि स्ट्राइक की नौबत भाई भौर मेरा कहना है कि उत छोटे-छोटे ग्रीवियान्सेज को दूर करने से भापका काम भासानी से चल सकता है।

दूसरी बात यह है कि रेल**वेज जब बनाई** गई थी तो उस समय में भाबादी भी कम थी ग्नौर जिन लोगों ने उसको बनाया था उन्हें जनता की मुविधा देखने की गरज भी नहीं थी। उन्होंने एट रैंडम जहां चाहा लेबिल कार्सिंग देदी कहीं पर तो एक-एक मील पर **लेवि**ल कासिंग है भौर कहीं चार, चार मील पर भी नेविल कासिंग नहीं है। धब धाज पहले की माबादी ਸੀ बहुत ঘষিক मपेक्षा बढ़ गयी है भौर गांव भी बढ़ गए हैं यह भाव-ध्यक हो गया है कि लेबिल कार्सिंग प्रधिक बनाए जाएं। धब इसके लिए यह कहा जा सकता है कि नये लेबिल कौसिंग तो तभी बनाए जा सकते हैं जब गांव वाले पैसा दें या स्टेट गवनं मेंट पैसा दे लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस वक्त यह बनते थे उस समय भगर कोई सिम्पेबिटिक मरकार होती तो एटरंडम न बना कर बल्कि एक व्यवस्थित भाषार पर लेविल कामिंग्स भौर स्टेशन्स उसने बनाये होते । मुझे मालूम है कि छारा से पोपासमहोता **के बीच** में चार मील तक कोई सेविल कार्मिंग नहीं है। इस सम्बन्ध में लिसने पर यह कहा जाता है कि रेलवज का कल यह है कि पहले नार्व जमा कीजिये, या स्टेट गवर्नमेंट से जमा कराइए । धक्सर यह भी देखा जाता है कि कहीं-तहां तो एक माइस में दो-दो सेविस क.सिंग हैं भौर कहीं-कहीं चार माइस तक एक भी नहीं देते हैं। मैं यह निवेदन करना बाहता हं कि यह रेसबे प्रशासन की ज्यादती है भीर उसको इस मोर

जानता हूं कि उसको देना उनके हाथ में नहीं है । घब घगर मैं नई लाइन्स की मांग करूं तो वह पहले प्लानिंग कमिशन में जाएगी घौर न मालूम घौर कहां-कहां घूम कर जाएगी घौर तब जाकर कहीं वह चीज होगी । नई लाइन को देना यह उनके हाथ में नहीं है । लेकिन मैं उन चीजों के बारे में जो कि उनके हाथ में है घौर जिसकी कि वजह से रेलवेज की बदनामी होती है घौर उसकी प्रगति में बाघा पड़ती है, जिक करने चला हूं घौर में चाहता हूं कि मंत्री महोदय उन खराबियों को दूर कर दें ।

सबसे पहली मावश्यकता किसी भी न्यापार या कर्माशयल सर्विस के सफलतापूर्वक चलने की यह है कि उसका स्टाफ सैटिसफाइड हो । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इसमें मुझसे सहमत होंगे कि रेलवेज के स्टाफ में मगर कुछ लोग भी डिटरमिंड डिस्सैटिसफाइड हों तो वह झापके काम में बाघा पहुंचाते हैं। ग्रब रेलवे कर्मचारियों में ग्रसन्तोष होने के मामुली-मामुली कारण रहते हैं। कर्मचारियों से कोई उनके झफसर रंज हो गये नाराज हो गये भौर वे भ्रफसर महाशय भ्रपने उन कर्म-चारियों का रिकार्ड खराब करने लगे भौर उनको नुक्सान करने की तलाश में रहते हैं भौर किसी दूसरे कसूर में उनको हटा दिया जाता है। वे बेचारे भपनी फरियाद लेकर हमारे पास झाते हैं। हम लोग इंडिविजुझल केसेज मापके सामने लाने में डरते हैं भौर बहुत कम केसेज मापके सामने लाते हैं। भाज हालत यह है कि उन को ग्रीवियांसेज के दूरस्त होने में काफी समय लग जाता है भौर जिसका कि नतीआ यह होता है कि उन बेबारों की जितनी भी बूंजी जमाहोती है वह सब इधर से उधर दौड़ने में सर्च हो जाती है। इसलिए में चाहना हूं कि रेलवे बोर्ड इस भोर घ्यान दे भीर उनके ग्रोवियान्सेज जल्दी से जस्दी दूर करने की व्यवस्था करे। उनमें भाज जितना समय नहीं लगना चाहिये । मुझे ऐसे केसेज का इल्म है जो कि पिछले पांच वर्षों से पैटिंब है भौर ने नेवारे दिल्ली, गोर**य-**

[पंडित द्वा∙ ना• तिवारी] भ्यान दे कर लोगों को सुविधा देने का प्रयत्न करना चाहिये ।

हम देसते हैं कि रैलवे प्रोटैक्शन कोर्स के होते हुए भी गाड़ियों में चोरियां होती हैं प्रौर रेलवे की चीजें जाती हैं । उनको कौन प्रौटैक्ट करेगा ? प्राखिर रेलवे प्रौटेक्शन कार्स किस लिये है । मैं समझता हूं कि रैलवे का कोई भी सामान बिनः रेलवे कर्मचारयों की कनाईवेंस या एक्टिव को-प्रापरेशन के चोरी नहीं हो सकता है । इसालये प्रावध्यकता इस बात की है कि रेलवे प्रोटैक्शन फोस को इस सरह प्रागंनाइज किय। जाये कि हमारी नेशनल प्रापर्टी बरबाद न हो सके ।

कुछ लोग तो सामान चोरी करते हैं, लेकिन रेलवे बोर्ड टाइम की चोरी करता है। **वे स्टील टाइन** । म्राप जरा पांच छः बरस पहले के टाइम टेबिल मौर माज के टाइम टेबिल में तूलना कीजिये **भौ**र देखिये कि टाइम में कितनी चोरी हई है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि एक्सप्रैंस २२ घंटे के बजाय ग्रब २४ घंटे में चलती है। यह टाइम की चोरी है। यह तीन षंटे रेलवे विभाग ने हमारे ले लिये हैं । रनिंग टाइम को बढ़ा दिया गया है मौर केत जाता है कि गाड़ियां पंक्चमल हैं। क्यों हैं ? में ने इसको स्कृटनाइज किया कि रनिंग टाइम बढ़ गया है झौर कहीं-कहीं इतना स्टोपैज हो गया है कि यदि गाड़ी लेट भी हो जाये, तो भी वह मेकअप कर सकती है। रेलवे प्रशासन को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि लम्बी यात्रा करने वाले व्यक्ति सफर से जब न जायें भीर उनका बहुत समय बरबाद न हो। पहले पटना से दिल्ली बीस चंटे में जाते ये भौर भव व।इस घटे में । इसी प्रकार पहले गोरलपूर से छपर। जाने में पांच घंटे सगते थे, जब कि भव सात, भाठ घंटे लगते हैं मैंने इस सम्बन्ध में एक रेलवे घाला घाफिसर से पूछा भीर मझे बताया गया कि भगर भाष-को ठीक समय दिया जाता, तो आप को स्टेजन पर बैठना पडता । घब घाप इतमीनान से स्टेकन पर मा तकते हैं। भव ज्यादा टाइम दे दिवा गया है भौर माप स्टेकन के बजाये घर पर बैठ सकते हैं? इस में क्या हानि है? यह जवाब सुन कर मैं भवाक् रह गया।

जहां पर रेलवे विभाग को एपरोच रोड्ज बनानी हैं--स्टेट गवर्नमेंट को नहीं, वहां पर भी कोई प्रगति नहीं हुई है। एपरोच रोड्ज इतनी खराब हैं कि उन पर बैलगाड़ी भी चलना मुध्किल है। हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब बड़े एनथ्यूजिएस्टिक हैं। वह एन॰ई॰ रेलबे में झा कर एपरोच रोड्स को देखें।

श्वी शाहनवाज सां: जो एप्रोच रोड्ज स्टेशन की हुदूद के मन्दर हैं, उनके लिए ही हमारी जिम्मेदारी है।

पंडित हा॰ ना॰ तिवारी : मैं उन्हीं की बात कह रहा हूं । जो लाइन से उतर कर फाटक के भीतर हैं, मैं उनके सम्बन्ध में ही निवेदन कर रहा हूं । क्वाटर्ज के विषय में हम जानते हैं कि ग्रभी वे बन कर मुकम्मल नहीं हुए हैं कि चुने लग गये हैं । एप्रोच रोड्ज के लिए पैसा दिया जाता है, लेकिन वह कसे सर्च किया जाता है भौर वे रोड्ज केसे बनती हैं, यह मैं नहीं कह सकता ।

इन छोटी-छोटी बातों पर मैं माननीय मंत्री महोदय का घ्यान इस लिये झार्काघत करना चाहता हूं कि वह इस तरफ तवज्जह दें। बह बिना खर्च किये इस को ठीक कर सकते हैं।

भी झाहनवाथ को : वगैर सर्च के कैसे ?

पंडित हा॰ ना॰ तिवारी : प्रश.सन के पास रूपया है धौर वह प्राविजन करता है, लेकिन उसको ठीक तरह से सर्च नहीं किया जाता है, रुपया बेस्ट किया जाता है। एप्रोच रोष्ड के लिये पैस। है, वह सर्च होता है या नहीं भौर उचित रूप से खर्च होता है या नहीं, इस तरफ तवज्जह करने की मावस्यकता है। इसी प्रकार ट्रैविल का टाइम बढ़ा दिया मया है। मैं नहीं समझ पाता कि उस को ठौक करने में क्या खर्च है। स्टाफ की किसी भ्रपील का फौसला करने के लिये भी किसी खर्च की जरूरत नहीं है ----सिर्फ तवज्जह की जरूरत है। पांच-पांच बरस से केसिज लटके हुए हैं। या तो हमारी बुद्धि भौर हमारी भाषा ऐसी नहीं है कि हम उनको समझा सकों, या वह ही समझ नहीं पा रहे हैं।

भी झाहनवाज सां: मैं तो यह जानना चाहता था कि एप्रोच रोड्स कैसे बगैर सर्चके बन जाती हैं।

श्वी राजेन्द्र सिंह (छपरा) : माननीय मंत्री जी ने ग्रथन उत्तर में काह, है कि जहां पर एप्रोच रोड नहीं हैं, वहां पर रेलवे विभाग नहीं, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट ग्रोवर-क्रिज बनायेगी, छपरा में, जहां से मैं भौर श्री तिवारी झाते हैं म्युनिसिर्थलिटी की भौर से एपरोच रोड बनी हुई है, लेकिन फिट्र भी तीन बरस से झोवर-क्रिज नहीं बना है ।

भी झाहनवाख लांः म।ननीय सदस्य की बारी भी मायगी ।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : बहुत से माननीय सदस्यों ने कैटरिंग के बारे में कहा है। स्टेशन पर जो बीजें बेबी जाती हैं, उनमें पान भी है: पान का दाम दो पैसे रख दिया गया है— चाहे कैसा भी पान हो। हम पान खाने बाले हैं और हम जानते हैं कि कितना खराब पान मिलता है। पान में कोई नफा भी नहीं है। प्रशासन इतना काम ले लेता है कि वह उस-को मैंनेज नहीं कर सकता है। जो खाने की बीजें स्वास्प्यवर्षक हों, उनकी व्यवस्था तो बह बेशक करे, लेकिन पान, बीड़ी, सिगरेट का काम लेने से क्या फायदा है?

वी राजेना सिंहः एक जी रिफैसमेंट रूम भण्डी तरह से नहीं चल रहा है। पंडित हा० **ला० तिवारी : ना**ननीय सदस्य मेरा डाइम न सें ।

I am not making any demand. I am simply drawing your attention to those things, that they can do easily without any expenditure.

ग्रब एक भौर समस्या की भोर में माननीय मंत्री का भ्यान मार्कीयत करना वाहता हं। हम देखते हैं कि दक्षिण में एक गांव है और उत्तर में गांव बालों की जमीन है जिनके बीच में विलेज रोड है और जब रेलवे विभाग उस रोड को एक्वायर कर लेता है तो उन लोगों के लिये जाने का रास्ता नहीं रहता है। में पहाडीचक गांव का जो सोनपूर स्टेशन के निकट है उदाहरण देना चाहता हं । वहां पर वक्षिण में कई गांव हैं और उन के सेत हैं उत्तर में, भौर मकान हैं दक्षिण में । बीच में रेलवेज ने जमीन ले ली है । **भव** वे लोग कैसे झांए जायें । उनका मामला कई बरस से चल रहा है। रेलवे बिभाग ने वहां चारों तरफ़ दीवार बना दी है। इससे उन लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पडता है । माननीय मंत्री जी को इस समस्या की भ्रोर भी ध्यान देना चाहिए।

प्रब में यह बताना चाहता हूं कि एक लेबिल कार्सिंग के तीन-तीन बंटे बन्द रहने से लोगों को बहुन कठिनाई होती थी। मैं ने इस सम्बन्ध में रेलचे मिनिस्टर साहब को प्रैम किया, तो प्रोवर बिज ऐसी जगह बना दिया गया कि वहां के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुपा है। यदि उन को पूर्व के बजाये पश्चिम में बना दिया जाता, तो लोगों को प्रबध्य फ़ायदा होता। मेरे कहने का नात्पर्य यह है कि हम जो मुझाव देते हैं, उनको इम तरीके से एक्सीक्यूट किया जाता है कि उसने मोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता है। यदि उस घोवर बिज को उननी ही दूर स्टेशन मे पश्चिम की तरफ बनावा जाता, जितना कि बह पूर्व की तरफ बनावा नया है, तो उसी [पंडित डा॰ ना॰ तिवारी]

स्तर्च से स्टाफ़ झौर गांव वालों दोनों का फ़ायदाहो जाता। भव सुना है कि वहां जो भोवर बिज है, उसको म्राइलैंड तक, सड़क तक ले जाने की बात है । मैं कहंगा कि उसको स्टेशन के पश्चिम में कर दीजिये भौर सब-वं जो सडक पर जाने के लिए बना है उसे कनेक्ट कर दीजिये तो ज्यादा भच्छा होगा । उसमें खर्चा भ्रापका ज्यादा नहीं पड़ेगा । इसी खर्चे में ग्रापका काम चल जाएगा । मगर मापने ऐसा नहीं किया तो गांव वालों का काम नहीं चलेगा भौर मुफ्त में झझट खड़े होंगे। प्रभी भी एक केस चल रहा है इसके बारे में । कई बार मैंने **भौर हमारे दोस्तों ने रिप्रिजेंट किया है लेकिन** कुछ भी नहीं किया गया है। म्राजकल हो क्या रहा है, इस झोर झाप ध्यान दें। नीचे से जब फाइल चलती है, क्लर्क से जब फाइल चलती है तो वह जो नोट लिख देता है उसको जपर तक देखने वाला कोई नहीं है । कोई यह नहीं देखता है कि फाइल में क्या है झौर क्या नहीं है। उसी नोट पर झाईर पास करते हुए चले जाते हैं । मैं कहुंगा कि इस को जरा ध्यान देकर देखा जाए कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं, कैसे उनको लाभ पहुंच सकता है . . .

भी शाहनवाच सांः फाइल वहां रहती है, लेकिन मार्डर बदल जाते हैं ।

पंडित हा० ना० तिवारी: नोट्स पर झाप झाढर देते हैं। झाप सोनपुर की फाइल को मंगा कर देखिय, उसमें क्या है। वहां की गवर्नमेंट ने क्या लिखा है, पुलिस ने क्या सिखा है, लोगों ने क्या लिखा है, गांव वालों ने क्या लिखा है। वहां पर जनरल मैनेजर देखने गए थे, हमारा उनके साथ सम्पर्क नहीं हो सका नहीं तो हम उनको बता देते कि किस बीज की झावश्यकता है।

यह जो दूबार्डस बेटर कंडिशंस झाफ ट्रेबल नामक पुस्तिका हमें दी गई है इसके

पेज ३६, भ्राइटम नम्बर ६ में छ: स्टेशनों के नाम दिए गए हैं जहां फुट ब्रिज या सब-वे बनने वाला है उसमें एक डिघवाड़ा स्टेशन भी है। इसके बारे में बहुत दिनों से लोगों की एक डिमांड चली मा रही थी। मुझे डर है कि इसको भी कहीं गलत ढंग से न बना दिया जाए झौर जिलना लाभ लोगों को होना चाहिये, उसके फलस्वरूप वह न हो सके । यहां पर ग्रोवर-ब्रिज की उतनी जरूरत नहीं है जितनी कि झंडरझिज की है। लाइन के दक्षिण में विलेज है। दक्षिण में उसके गेंजिज है । वहा उसका एक्सपशन नहीं किया जा सकता । दक्षिण में एक्सप्रेंशन की कोई गुंजण्इश नहीं है। एक लिक रास्ता विटवीन स्टेशन एड मालगोदाम हो जाए तो लोगों को फायदा हो सकता है, उनको भाधिक सुविधा हो सकती है। लेकिन मुझे डर यह है कि धंडर ब्रिज न बना करके कहीं भोवर-क्रिज बना दिया जाए भौर पश्चिम न बना करके कही पूर्व बना दिया जाए ये सब चीज हैं जिनकी मोर मापका घ्यान जाना चाहिये । झापको चाहिये कि इन पर **धा**प विचार क**रें भौ**र जिसमें भ्रधिक सुविधा हो वही काम करें।

मैं कोई नई डिमांड पेश नहीं कर रहा हूं भौर न कोई ऐसी डिमांडपेश कर रहा हूं जिसमें घषिक रुग्या खर्च हो। जितना भापका प्राविखन है, उसी को इस तरह से खर्च करने की बात मैं कह रहा हूं जिससे जनता को घषिक लाभ हो सके। जिस तरह से मैंने भापको काम करने के लिए कहा है भगर भापने उस तरह से उसको किया तो लोगों को संतोष होगा भौर वे भापकी जय जयकार करेंगे।

मैं भाशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिए हैं, उन पर भाप विचार करेंगे भौर जो कुछ भाप कर सकते हैं, करने की कोशिश करेंगे । मेरे सुझावों में भ्राधिक पैसा सर्च करने की कोई

for Grants (Railways)

4262

बात नहीं है, इस वास्ते मैं ग्राशा करता हूं कि ग्राप उनको स्वीकार कर लेंगे ।

Shri M. B. Thakore: I thank you yery much for giving me some time to speak on the Railway Demands. At the outset, I congratulate the Railway Administration for the excellent work that they have done.

Shri Rajendra Singh: Are you thinking of going over to the other side?

Shri M. B. Thakore: No, I shall never go.

I unders and from the speech of the hon. Railway Minister that on account of political, economic and social reasons, Government have decided to construct new lines in the south. I would request the hon. Minister that on the same basis, he should consider the question of constructing railway lines, or. I would say, links in Gujarat.

In North Gujarat especially, Panchmahal. Dang, Surat, Navsari and Saurashtra areas are very backward; they are mostly backward and undeveloped. I would request the hon. Minister specially to construct a few lines there, because there is no transport facility nor any conveyance available there at the time of monsoon. North Gujarat is on the border with Pakistan, and if it is developed it will be most useful in the future.

In North Gujarat, there is a Kutch desert that is advancing towards the and east. towards Banaskantha Mehsasa districts. If the Railway line from Kandla to Palanpur is doubled, I think the area will slowly develop, and the Kutch desert also will be prevented from advancing. I spoke about this in 1959 in the course of the debate on the Railway Demands, but nothing has been done up till now. At the last meeting of the consultative committee. I was discussing this matter, when the hon. Deputy Minister Shri S. V. Ramaswamy was there, and he wished that I should speak about 2134 (Ai) L.S.D.-7.

this on the railway budget, and he did not allow me to speak about these lines earlier. These links are not more than 7 miles in length, in any case, not more than 20 miles. The expenditure also will not be very much. I suggest that the following lines be constructed during the Third Five Year Plan. The first line is between Kherula or Vijapur to Himmatnagar. Then, there is a line up to Harij. If it is extended to Radhanpur via Sami, it will not be more than 20 miles. I do not think there is any river or any nullah where it would be necessary to build a bridge. Thirdly, I would suggest 8 line between Kakoshi to Sidhpur or Chhapi, which is only a distance of about six to seven miles. There is a great demand from all over these villages Kakoshi and Chhapi for this line. Then, fourthly, there is a line up to Vadnagar. From there, I would suggest the extension of the line via Sundhya, Ranchodpur, Unjha, Balisana to Patan. This is a link which is not more than 20 miles. I do not think there is any big river in between.

Then, there is need for a small link, which I always advocate, and that is from Tranga Hill to Timba. I have already written many times to the hon. Minister, because near Tranga Hill, there is a Jain temple, and many of the passengers or pilgrims go there. I think there are lines, but the trains do not go up to Timba; they go only up to Tranga Hill.

The second point that I want to make is regarding the imposition and collection of fine at Sidhpur railway station and other stations. I really wonder why there is no overbridge there. I have written on this matter many times. I have seen the General Manager and even the Minister talked about this in the consultative committee, but no steps have been taken about this foot overbridge. They say that they have written to the Gujarat Government, but there is no reply. Since 1957, the reply is the same. And in 1961 also, the reply is the same, and there is no change. I do not know

[Shri M. B. Thakore]

whether the Central Government, especially the railways have sent any reminders to the State of Gujarat or The municipality is ready to not. construct the approach road, but there is no action taken regarding the foot overbridge up till now. In the absence of this overbridge, when the villagers pass from the station and cross the railway lines, they are caught there by the police and taken to the magistrate, probably first class, I do not know, who summarily tries and imposes a fine, and if these persons are not able to pay, they are sent to jail. I asked a question of the hon. Minister of Railways, but he has replied in the negative. I really wonder how he got that information. I have seen with my own eyes a person looking like я Magistrate imposing and collecting very heavy fine, Rs. 5 and Rs. 10, and if you argue, Rs. 20. I know that the First Class Magistrate of Sidhpur was also fined, and even he had to pay it.

15 hrs.

Shri Shahnawaz Khan: Did he travel without ticket?

Shri M. B. Thakore: There was no question of travelling. He was crossing. There is the Sidhpur mill and other mills and villages are on the other side of the station.

Shri Narasimhan (Krishnagiri): So it was trespass.

Shri M. B. Thakore: Yes, may be.

Shri Narasimhan: Running the risk of being run over.

Shri M. B. Thakore: As I told you, even a First Class Magistrate was fined. Since very long, there was no foot overbridge there.

Mr. Chairman: He was fined not because he was a Magistrate.

Shri M. B. Thakore: He crossed over.

Mr. Chairman: He committed an offence.

Shri M. B. Thakore: My hon. friend, Shri Shahnawaz Khan, denied that there was imposition and collection of any tax.

Mr. Chairman: It is not a tax.

Shri S. V Ramaswamy: It is a fine, not a tax.

Shri M. B. Thakore: Yes, fine. You may refer to unstarred question No. 1317.

Shri Narasimhan: Kindly read the question and answer.

Shri M. B. Thakore: The question was:

(a)" whether it is a fact that heavy fine is imposed on the ignorant and innocent villagers and others who cross the railway station at Sidhpur and other stations on the Western Railway on the plea that they have no platform passes or tickets with them; and

(b) "if so, the total fine collected during 1959-60 and the number of persons sent to jail in this connection"?

Shri Shahnawaz Khan, the Deputy Minister, answered:

(a) "No.

(b) Does not arises".

According to him. there was no imposition of fine.

Shri Narasimhan: Let him raise a half-hour discussion on it.

Shri M. B. Thakore: The second point I would like to make is regarding some servants of the canteen contractors at Ambliyasan and Kalol. In this regard. I met Shri Shahnawaz Khan and the General Manager so many times, but they did not listen to me. It is the ruling of the Speaker that if there are difficulties in regard to administrative details, we must write to the Minister or see him. That was why I saw him so many times. But unfortunately no steps have been taken. I spoke about this in the Railway Budget discussion of 1959, and the hon. Minister was pleased to state that if there was any vacancy, they would be absorbed. But uptil now, no steps have been taken. I again request him through you to look into the matter and give them work.

Mr. Chairman: The hon. Member has taken more than ten minutes.

Shri M. B. Thakore: I did not speak in 1960. So kindly give me some more time.

Mr. Chairman: I am not responsible for that.

Shri S. V. Ramaswamy: It is timebarred!

Shri M. B. Thakore: Regarding 'ny cut motion No. 378 about the need to shift the headquarters of the Western Railway from Bombay to Ahmedabad, I do not understand why after the separation of Gujarat and Maharashtra, still the headquarters of the Western Railway has not been shifted.

Shri Shahnawaz Khan: The railway headquarters has nothing to do with the State headquarters.

Shri M. B. Thakore: That is true but the majority of the lines and the trains are passing through Ahmedabadup and down. I think it will be most advisable for the Railway Administration to shift the headquarters of the Western Railway to Ahmedabad. I think Shri Ram Krishan Gupta also suggested that the headquarters of the Western Railway may be shifted from Bombay to Ahmedabad or Ajmer.

Shri T. B. Vittal Ras (Khammam): That is what the Estimates Committee also recommended.

Shri Shahnawas Khan: What is his proposal—Ahmedabad or Ajmer?

Shri M. B. Thakere: Ahmedabad. There they will get buildings and get land on which they can construct quarters.

l) for Grants 4266 (Railways)

Then I would talk about reducing overcrowding on the branch line from Mehsana and Ahmedabad. I have written so many times to the Deputy Ministers and the Minister. I have seen the General Manager also. But they have not taken any action on all I say my suggestions. that there should be a double line from Ahmedabad to Abu Road and Marwar, that is, Ahmedabad to Marwar. Then I suggested doubling the line from Kandla to Palanpur. Then I recommended the introduction of some more trains from Mehsana to Abu Road and from Ahmedabad to Mehsana. Also on all branch lines they should at least attach two or three bogies more in the summer season.

Mr. Chairman: Shri B. D. Mishra.

भी भ० बी० मिभ (केसरगंज) : सभापति जी, रेलवे मंत्रालय ने सर्वतोमुखी उन्नति की है इसमें कोई सन्देह करने की बात नहीं है । लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे माननीय सदस्य के भांकड़ों के बताने के बाद यह निध्चित है कि कर्मचारियो की संख्या में जिस कदर वृद्धि की गयी है उननी ही देखरेख में कमी हो गयी है ।

जहां तक देखरेख की बात है, मैं ममझता हूं कि अधिक से अधिक कर्मचारियों के होते हुए भी सफाई में भी उतनी ही कमी तजर आती है जितनी कि अभी इतने कर्मचारियों के होते हुए नहीं होनी चाहिए।

भी मू॰ चं॰ चैन (कैथल) इन सहकमे में मंत्री **मौर चा**हिए।

भी भ० दी० मिभा इस महकमें में नती भौर चाहिए, यह माननीय सदम्य का सुआव है मै तो केवल इतना ही कहना कि पर्याप्त मोग मौजूद है, प्रायध्यकता लिर्फ देसरेस की भोर प्यान देने की है।

भी जाहनवाम जा : यह तुन जिया गया ।

भी भ० दी० मिश्च: जहां मेंने इस डिपार्टमेंट की सवतोन्मुखी उन्नति की बात कही वहां मुझे एक संस्कृत की कहावत याद श्राती है जो कि इस प्रकार है:

राजन् कनक धाराभि ः त्वयि सर्वत्र वर्षति क्रभाग्य छत्र संछन्ने मयि नायान्ति विन्दव : ।।

भ्रर्थात्, भ्रापकी सब तरह उदार बुद्धि होते हुए भी भौर सब तरफ सोने की वर्षा होते हुए भी मेरे ऊपर कनक की एक बूंद तक नहीं भ्रायी । यह कहावत मुझे बांच लाइनों के सम्बन्ध में कहनी पडी है ।

रेलवेज का मेन लाइंस की तरफ ध्यान गया है। लेकिन जहां तक कांच लाइंस का सम्बन्ध है, बी० एन० डब्लू० रेलवे जब चल रही थी, जब कम्पनी की यह रेलवे थी, वह म्राज तक उसी म्रपनी पुरानी मवस्था में पड़ी हुई है। एक, एक स्टेशन ऐसे बने हुए हैं जहां सम्भवतः स्टेशन मास्टर के खडे होकर टिकट बांटने के प्रलावा भौर कोई जगह ही नहीं है । मेन पिछले साल भी प्रापना ध्यान दिलाया था कि पूर्वोत्तर रेलवे में बहराइच जिले में नान-पारा से कतरनिया घाट जो लाइन जाती है उसमें एक भी स्टेशन ऐसा नही है जहां पर कि किसी भी समय जाड़े में, गर्मी में प्रथवा बरसात में १० आदमी भी इकट्ठे खडे हो सकें। पिछले साल मीहपुरवा स्टेशन पर एक बहत छोटा सा शेड बनाया गया है जहां कि में समझता हूं कि ४० झादमी बड़ी मुझ्किल से बैठ सकेंगे, लेकिन वहां यलाया उस छोटे से घोड बनाने के भौर किसी किस्म का सूधार नहीं किया गया है । वहां पर कोई भी किसी प्रकार का पानी का प्रबन्ध या वर्षा भ्रथवा ग्रीष्म ऋतु के कोप से बचने का प्रबन्ध भयवा स्थान नहीं है ।

इसके मलावा माप देखें कि बहा पर गाड़ियों की क्या स्थिति है। मैं जानता हूं कि कभी-कभी हमारे जनरल मैंनेजर जो कि उस रेसबेज के हैं वे बहां पर मपनी सुषज्यित गाड़ियों के भ्रन्दर जाते हैं लेकिन वह गाड़ियां जिनमें कि जनता चलती है उनकी क्या भ्रवस्था है । ग्रगर में भ्रधिक न कहूं तो यह कह सकता हूं कि सम्भवतः इन पांच, दस वर्षों में उनकी कोई मरम्मत नहीं हुई है भौर वह उसी भ्रपनी पुरानी हालत में चल रही हैं ।

तृतीय श्रेणी की गाड़ियों के सम्बन्ध में तो सम्भवतः रेलवे प्रशासन का घ्यान ही कम जाता है । मैं देखता हूं कि फस्ट भौर सेकेंड क्लाम की गाडियों की भी कमोवेश वही म्रवस्था है। लखनऊ में नैपालगंज रोड तक जो एक डिब्बा लगना है उस डिब्बे को यदि माप देखने की भोषटा करें तो भ्राप पायेंगे कि उसमें भीड़ अत्यधिक होने के कारण जगह बहुत कम रहती है। गोंडे में एक बजे या दो बजे वह गाडी पहुंचती है इसलिए हर ब्रादमी चाहना है कि वह उसमें बैठ कर नैपालगंज तक पूरी रात का सफर कर सके । मेरा सूझाव है कि इसके लिए एक पूरी बोगी अलग में उसमें लगनी चाहिए । अब हालत यह है कि थई क्लाम में तो किसी तरीके से जगह नहीं मिलती । फर्म्ट क्लाम और सेकंड क्लाम में भी करीब-हरीब यही हालत है । बोगीज की सम्भवतः दो-तीन वर्ष से सफाई नहीं हई मालूम होती है। कोचेज की भी बुरी हालत है। मेरा कहना है कि ब्रांच लाइंस की तरफ मापका विशेष ध्यान जाना चाहिए **धौर उनके स्टेशनों** भौर गाड़ियों के सू**धार की तरफ विशेष क**प से ध्यान दिया जाना चाहिए ।

में तो भपने तई इसको एक बहुत बड़ी सुविधा समझता हूं कि स्टशनों पर साफ मिट्टी रखने की व्यवस्था की गई है। उससे मी हुछ काम जलता है क्योंकि यात्री लोग सौधादि खाने के बाद हाथ घोने के लिए उतरते हैं धौर उम्हें मिट्टी की जरूरत पड़ती है लेकिन धापने मी देसा होगा धौर मेरा भनुमव है धौर इसके सिए मैंने समय-समय पर स्टेशन मास्टर से कहा है कि क्यों साहब यह यहां पर मिट्टी,

for Grants (Raikoays)

रखने की जगह तो झापने बना दी है लेकिन यह नहीं देखा जाता है कि वहां पर मिट्री बरी भी है कि नहीं झौर ८, ८ रोज तक मिट्री नहीं रक्सी जाती है । म्रापको इसकी वेखरेख रखनी चाहिए कि यह जो मिट्री की सुविधा प्रदान की गई है वह वास्तव में झपनी जगह पर मौजूद भी है कि नहीं । भगर रेलवे प्रशासन, जो सुविधाएं उसने जनता को दी है. उनके बारे में देखरेख बनाये रक्खे तो जनता को ग्रधिक से भ्रधिक लाभ हो सकता है लेकिन उनकी देखरेख की कमी है । मैं श्रापका ध्यान सभापति महोदय के जरिए दिलाना चाहता ह कि म्राप काफी रुपया खर्च कर रहे हैं, म्रापने मुविधाएं दी हैं, म्रापने किराये भी काफी बढा दिये हैं भौर इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि किराया भ्रापकी जेब में जाता है लेकिन जितनी मूविधाएं जनता को मिली चाहिएं उतनी ु उसको नहीं मिलती हैं । इसके लिए मैं भ्रापका ध्यान आकर्षित करना चाहता हु।

प्रथम श्रेणी भौर दितीय श्रेणी के लिए कंडक्टर्स मुकरंर हो गये हैं लेकिन तृतीय श्रेणी में ऐसी कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है। तीसरे दर्जे में बड़ी रेलपेल रहती है भौर हम देखते हैं कि बुढ़े भौर एक बुढिया दौड़ते हैं लेकिन गाड़ी नहीं पाते हैं भौर गाड़ी छूट जाती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि तृतीय श्रेणी के लिए भी कंडक्टर या किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाय जो कि उनको गाड़ी में बिठा सके। इसलिए मैं समझता हूं कि तृतीय श्रेणी में सुविधाओं के दिये जाने की भावध्यकता इ ।

इसके मलावा मैंने दो सुझाव भापके सामने मौर रक्खे थे । जिस समय माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मंत्रालय में काम कर रहे थे मैंने यह सुझाव पेश किया था कि जरनल रोड से बहराइच जिनग होते हुए सोहेलवा जंगल तक एक लाइन निकाली जाये। इस साइन के निकालने की चर्चा नी चली वी भौर सम्भवतः उसका सर्वे भी हो चुका था। मुझे पिछले साल भी यह कहा गया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सम्भदत इस पर विचार होगा लेकिन मुझे खेद है कि इस साल में भी मैंने उसे नहीं देखा है। मैं इस मबसर पर उसकी भोर पुनः मंत्री महोदय का घ्यान माकर्षित करना चाहता हूं मौर उसके बनने से जनता को काफी सुविधा होगी, कच्चे माल के लाने की सुविधाएं भी बहुत बढ़ जायेंगी मौर उसी के साथ-साथ रेलवे विभाग को भी प्रधिक से मधिक लाभ होगा।

कतरनियाघाट जो कि बहराइच जिसे में है वहां से कौडियालाघाट तक ६ मील का फासला है जिसके कि बीच में गेरूमा नदी पड़ती है तो मेरा सुझाव है कि इस नदी के ऊपर बीच में एक बिज बना कर रेलवे लाइन निकाल दी जाये तो उससे बड़ी सुविधा हो सकती है। पश्चिमी जिलों जैसे नैनीताल भीर सहारनपुर से बहां तक जाने की बहत सुविधा हो सकती है जब कि इघर गोंडा, लखनऊ घम कर बराबर जाते हैं। जहां घोड़े से खर्चे से प्रधिक सविधाझों और मधिक लाभ होने की सम्भावना है तो उस सर्चे की तरफ घ्यान देना चाहिए । इसलिए यह कोडियालाघाट पर जो बिज बनाने की बात है भीर उस पर से होकर रेलवे लाइन निकालने का सुझाव मैं भाषके सामने पहले भी दे चुका हुं भीर भाज फिर उसको बुहराते हुए भाषा करता हं कि माप उस तरफ म्राविक ध्यान देने की कोशिश करेंगे।

इसके प्रतिरिक्त हमारे कई भाइयों ने डिपार्टमेंटल कैन्टीन के बारे में भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किये हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले रेलवेज में जो ठेकेदारी सिस्टम चलता वा वह ज्यादा प्रण्डा था क्योंकि रेलवे के ठेकेदार को इस बात की चिन्ता रहती थी कि कहीं बाहक प्रर्थात् यात्री चिन्ता रहती थी कि कहीं बाहक प्रर्थात् यात्री चिन्ता रहती थी कि कहीं बाहक प्रर्थात् यात्री चीन्ता रहती थी कि कहीं बाहक प्रर्थात् यात्री लोग किसी तरह से भोजन से प्रसन्तुष्ट न हो जायें प्रौर वह सोचना था कि प्रगर हमारी चीर्वे प्रण्डी बनेंगी, सुविचा से मिलेंगी ग्रीर कम दाम में मिलेंगी तो मुनाफिर नीन प्रचिक नेने की चेप्टा करेंगे ग्रीर

[श्री म॰ दी॰ मिश्र]

ठेकेदार को श्रधिक लाभ मिलेगा । लेकिन जब से कैटरिंग का रेलवे की तरफ से खुद इंतजाम हुआ है और जैमा कि ग्रधिकतर लोगों का ख्याल है जिनके जिम्में यह काम है बह लापरवाही श्रौर कुछ उपेक्षा का भाव रखते हैं क्योंकि वह पेड सर्वेटस होते हैं, रेलवे से माहवारी तनख्वाह मिलती है श्रौर इमलिए बह उतनी मुस्नैदी श्रौर इंटरैस्ट मे काम नहीं करते । मैं चाहता हं कि रेलवे प्रशासन को इम कैटरिंग के काम के ऊपर अधिक देखरेख करनी चाहिए ।

एक माननीथ सदस्य ने जो रोटी का स्टेन्डर्ड रखने का मुझाव दिया था वह उचित ही था क्योंकि उसके प्रभाव में थोड़े भे प्राटे के चार फुलके हलके-हलके बना कर रख दिये जाते हैं और जो लोग कि दो, दो और चार, चार मर्त्तवा नाश्ता नहीं करते उनके लिए वह नाकाफी होता है । फुलके जो दिये जायें वे इतनी लोई के तो हों कि जनसाधारण के लिए पर्याप्त हों । इसेलिए मेरा निवेदन है कि रेलवे प्रशासन को प्रपने इस डिपार्टमेंटल कैटरिंग के बारे में जरा ज्यादा घ्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि जनता को उचित मुनासिब दाम पर पर्याप्त भंगन प्राप्त हो ।

इसके प्रतिरिक्त एक बात मुझे प्रौर कहनी है । रेलवेज के बारे में जनश्रुति यह है कि यहां पर नियुक्ति के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लिये बिना किसी प्रकार भी सफलता नही मिल सकती है । प्रब हमारे देश में हर जगह भ्रष्टाचार है, हर विभाग में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार है ऐसी खनश्रुति है लेकिन यह जनश्रुति रेलवे के बारे में भ्रपेक्षाकृत कहीं भ्रषिक है भौर मुझे रेलवेज के जिम्मेदार भादमियों के ढारा मालूम हुमा है कि साहब इस विभाग में प्रवेश पाने के लिए भ्रष्टाचार की भावश्यकता पड़ती है । मै भ्रपने रेलवे मंत्री महोदय का म्यान इस झोर

विशेष रूप से ग्राकर्षित करना चाहता ह । जब ग्रापके यहां इतनी जगहें होती हैं और इस कदर पिछले दो, तीन वर्षों में नियक्तियां हई हैं तो इस बात की बहत जरूरत है कि इस मोर घ्यान दिया जाये कि वास्तव मे वे ही लोग नियक्त हों जो कि उसके लिए योग्य हों । उपयुक्त नियुक्तियां न होने का ही परिणाम हम देखते हैं कि एक गाडी लाइन पर खडी होती है मालगाड़ी उघर खडी होनी चाहिए लेकिन ठीक पटरियों की बदली न होने के कारण और सम्बन्धित कर्मचारियों की लापर्वाही के कारण गाडियां ग्रापस में टकरा जाती है और जान-माल का बहत नुक्सान हो जाता है। मेरा तो अपना मत है कि अगर नियक्तियां करते समय साववानी वर्ती गई होती और उपयुक्त पात्रों को ही नियुक्त किया जाता तो ऐसी गलतियां नहीं हो सकती थीं। इसलिए मैं आपका इस ओर ध्यान आकर्षित करता चाहता हूं कि नियुक्तियों के सम्बन्ध में जो यह अपवाद या जो जनश्रति चल रही है उसको दूर करने की पूरी चेप्टा की जाये। इन शब्दों के साथ में भ्रपनी चर्चा समाप्त करता हं।

Shri Harlsh Chandra Mathur (Pali): Mr. Chairman, Sir, I will not add to the long list of railway lines demanded for new construction. Not that Rajasthan has not got such a demand. I also appreciate this demand coming from the various quarters in an underdeveloped country. I will confine my observations to the working of the Railway Board, and to certain important matters of policy pursued by the Railway Board.

I have no hesitation in conceding that since 1945, when the railways were in a completely ramshackle condition, they have made vast improvements, and they have gained in strength from year to year. The progress has been a really very strike in cortain directions, particularly the production side, where we almost expect to gain self-sufficiency, and where our demands for foreign exchange have been very considerably reduced. This all goes to the credit of the railways, and the authorities from the International Bank and others who have come here have also paid handsome tribute to the railways.

I fully concede that we have got to pin-point our attention to certain very important measures. You will remember that on the floor the House, more than a year back, in answer to more than one question, the hon. Minister of Railways said that we were selfsufficient in wagons, that we were in a happy position to export wagons. It is just the same as at the end of the First Five Year Plan we were saying that we were self-sufficient in food and that there was no danger. We are planning in a haphazard manner. Now, you find how we are bottle-necked in everything. We find ourselves handicapped at all steps, whether it is the movement of steel, or the movement of coal or of other things.

I was very much surprised when I was told today that the same unfortunate condition obtains in the matter of food also. As a matter of fact I had asked the question only from that point of view. Why don't you stagger the movement of your food when you are self-sufficient in food, when you The hon. have got food all over? Minister Shri Patil is giving us the impression that we are surplus in food at every place. So, I thought we might stagger the movement of food so that certain wagons could be released to facilitate the movement of other items.

We have had explanations on this matter from the hon. Minister of Railways as also from the hon. Minister of Steel, and Mines. But I have no hesitation in saying that nobody in this House feels at all satisfied. Nobody seems to be at fault. The Railways say that they have done their best, that they have fulfilled their targets. The hon. Minister of Steel, Mines and Fuel says that everything is going according to plan, that we are in the best of co-ordination. If both of them have been proceeding according to plan and if everything is going on in full coordination, what is all this trouble about? We find 13 million tons of coal lying at the pit-heads.

When I went down to the south, in Bangalore and other places, to my very great surprise, I was told that the smalf-scale industries were completely starved. They could not get their demand of mere 300 tons for the last 6 months.

We are now so keen on our production and the entire future of our country. The entire economy of the country depends upon increased production. If such bottlenecks are created because of the most inefficient planning of the public sector-either it is in the Railways or it is in the Ministry of Mines and Steel-then, it gives a very great set-back. I do not know how the Railway Minister says that within the next 6 months the situation will ease. What will happen in 6 months' time? Could not that happen earlier? If the situation would be eased within the next 6 months why was not something done earlier? We have been bringing this matter all the time to the notice of the hon. Minister, that there is a bottle-neck, that the smallscale industry is suffering, that the large-scale industry is suffering. That is the most important matter. When that is so, we find them speaking, either from Jullundur or from Calcutta as if everything is all right. I could understand departmental heads speaking in that manner. But when hon. Ministers speak, we expect them to speak not for the Railways, not for the Mines or Coal but for the Government. When they speak for Government, I fail to understand how such dislocation has happened. The House must be taken into confidence and we must know why there was this dislocation and where there was no coordination.

We have just heard that a committee is going to be appointed under the chairmanship of the Finance Minister

[Shri Harish Chandra Mathur]

to devise ways and means to get over this bottleneck. It is all right. We very much welcome the appointment of that committee. But, I would strongly suggest that there should be a Standing Committee which should meet every month. This Standing Committee must represent at the highest level the Ministry of Commerce and Industry, the Ministry of Food, the Ministry of Steel, Mines and Fuel and also the Ministry of Railways; maybe under the chairmanship of the Minister of Railways. They must meet every month; they must take complete stock of the whole situation and we should know the co-ordinated position. We do not want the Chairman of the Railway Board issuing statements that the Railways have fulfilled their targets and the Controller saying something. I sent я certain letter and that letter has been forwarded to the Controller of Coal Movements. This is the state of affairs. The country will not be satisfled though the departmental heads may derive the satisfaction that they have fulfilled their targets. I therefore dmand that this Standing Committee should be appointed.

Another matter to which I would like to refer is the question of dieselisation. The hon. Minister of Finance has been telling us all the time that he wants a shift from diesel to petrol and that his taxation measures are devised with a view to that end, so far as road transport is concerned. I asked a guestion whether as a result of his taxation measures there has been any shift. He said that they were not at present in a position to give a really sound picture but they have every reason to believe that there has been a shift. The other day the Minister of Transport told us that the shift has been completely on the other side, that there has been a shift from pertrol to diesel, can absorb more tax please tax it; but do not let the country get wrong impression that we are switching on to a more inefficient type of fuel. If we are short of diesel is there

any justification for the Railways now to shift or to switch on to diesel?

The other day the Railway Minister said that we will have to lay 3 or 4 tracts. Have we examined the economy? I do not want vague general statements. We want to know definitely what is the examination which they have made of this important matter. When they are getting а diesel track of 3800 miles what is the economy of that? How is the entire future economy of the country going to be affected by this? What is our diesel requirement and what is the total foreign exchange we are spend on it? going to Has the Cabinet examined it. It is not enough that the Railway Board has examined it. Has the Cabinet come to conclusions? What would be the development so far as the entire economy is concerned?

There are two other matters to which I would like to refer about the working of the Railway Board. Certain hon. Members from the other side said that there has been a cut in the number of Class III and Class IV servants and asked why it should be so and why should there not be a cut in the number of officers. I think the criticism was not very sound. This cut in the number of Class III and Class IV servants in the Railway Board is very much welcome because the Railway Board is not functioning in the field. They are doing planning. When they are doing planning you do not need so many class IV servants, so many chaprasis to be appointed. This is very much welcome. But the Railway Minister also told us that he was going to effect a certain economy in the rest. He made mention of it last time. He said one of the Deputy Directors was being retrenched and further economies are being examined. I do not know whether they have examined the further economies and what those economies are.

I would submit that the Railways will not be able to do really much steamlining of their administration

4277 Committee on PHALGUNA 19, 1882 (SAKA) Land Acquisition 4278 Private Members' Bills (Amendment) Bill and Resolutions

unless and until they examine the entire structure of working. It is a strong feeling with me that there is unnecessary concentration of work in the Railway Board. It is true that there has been considerable delegation of power, from the General Managers downwards. There has been delegation of power for the efficient working of the Railways but there has been very little release of work. It is a general tendency; I do not blame anybody. The Members of the Railway Board may be very efficient but still ther is an unhappy tendency for the concentration of work and power.

If you refer to the Draft Outline of the Third Five Year Plan you will find that a very pointed reference has been made there that unhealthy tendency in the Secretariat is all over In every Ministry.

The Railways are, fortunately or unfortunately, no exception to that unhealthy tendency of concentrating power. I wish that there is a little relief of work and they concentrate themselves only on important work.

Mr. Chairman: Is he likely to take more time?

Shri Harish Chandra Mathur: Yes, Sir

Mr. Chairman: He may continue next time.

15-30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEM-BERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SEVENTY-EIGHTH REPORT

Shri Jhulan Sinha (Siwan): I beg to move:

"That this House agrees with the Seventy-eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 8th March, 1961."

*Published in the Gazette of India dated 10-3-61. Mr. Chairman: The question is:

"That this House agrees with the Seventy-eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 8th March, 1961."

The motion was adopted.

15.30} hrs.

ESSENTIAL COMMODITIES (FIXA-TION, REGULATION AND CONTROL OF PRICES) BILL[•] by Shri Narayanankutty Menon.

Shri Narayanankutty Menon (Mukandapuram): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for fixation, regulation and control of the prices of commodities which are essential for the life of the community.

Mr. Chairman: The question is:

"That leave b_e granted to introduce a Bill to provide for fixation, regulation and control of the prices of commodities which are essential for the life of the community."

The motion was adopted.

Shri Narayanankutty Menon: Sir, I introduce the Bill.

15.36 hrs.

LAND ACQUISITION (AMEND-MENT) BILL[•]

(Amendment by section 4) by Shri Keshava.

Shri Keshava (Bangalore City): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1894.

Mr. Chairman: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1894".

The motion was adopted.

Shri Keshava: Sir, I introduce the Bill.

Extraordinary Part II-Section 2.